छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **पंचम सत्र**

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025
(फाल्गुन 09, शक सम्वत् 1946)

[अंक 04]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2025

(फाल्गुन 9, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठसीन हुए}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल रात को बड़ी घटना हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अवसर दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकेण्ड।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था सही है। प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है, प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करायें। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- हमारे प्रदेश अध्यक्ष की रेकी की जा रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। जो भी विषय है, आपके पास प्रश्नकाल के बाद पूरा समय है। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- विषय बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय :- विषय की गंभीरता है, इसीलिए मैं आपको प्रश्नकाल के तुरन्त बाद अवसर दूंगा, पूरा समय दूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, रेकी कराया जा रहा है।

श्री उमेश पटेल :- दंतेवाड़ा पुलिस उनके घर की रेकी कर रही है। आप क्या करना चाहते हैं ? पुलिस के दम पर लोगों को डराना चाहते हैं ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, आप लोग क्यों डर रहे हो ?

एक माननीय सदस्य :- आप लोग व्यवस्था के खिलाफ जाकर बात कर रहे हो।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी करवा रहे हैं। एक जनपद सदस्य ...। (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी, एक मिनट। आपसे आग्रह है। प्रश्नकाल आप सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको अवसर दूंगा, मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [xx] करने की कोशिश की जा रही है। जनपद सदस्य को, हमारे जिला पंचायत सदस्य को डराने-धमकाने का काम किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के घर की रेकी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय :- कृपया प्रश्नकाल को बाधित ना करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डराने-धमकाने की राजनीति की जा रही है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री दलेश्वर साहू :- एडिशनल एस.पी. वर्मा कौन है ? कौन है ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित।

(11.06 से 11.18 तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
11:18 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे आदिवासी भाई दीपक बैज के घर की रेकी हो रही है। दंतेवाड़ा से पुलिस फोर्स रायपुर आकर रेकी कर रही है। क्या रायपुर में पुलिस की कमी हो गई थी? रायपुर के पुलिस वाले क्या कर रहे थे? दंतेवाड़ा की पुलिस यहां आकर रेकी कर रही है। (व्यवधान)

श्रीमती चातुरी नंद :- अध्यक्ष महोदय, आप इसको संज्ञान में लीजिये।

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- अध्यक्ष महोदय, यह [xx] है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार की कोई कोशिश नहीं है। ये लोग बिना नोटिस दिये जानबूझकर प्रश्नकाल में हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, [xx] [1]

श्रीमती अनिला भेंडिया :- अध्यक्ष महोदय, रायपुर की पुलिस क्या कर रही थी? यह लोग हमें डाराने-धमकाने का काम कर रहे हैं।

---

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में क्या हो रहा है, हमारे कांग्रेस पार्टी के आदिवासी...। (व्यवधान) [xx] [2] । अध्यक्ष महोदय, [xx] (व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा में हम लोग जनपद पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की स्थिति में है और इसलिये भारतीय जनता पार्टी ...। (व्यवधान)

श्री रोहित साहू :- अध्यक्ष महोदय, आपकी बहुमत ही नहीं है तो कहां से बन जायेगी ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप लोगों की हार हुई है तो बौखलाये हुये हैं । (व्यवधान) आप लोग बौखला गये हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल आपके लिये है, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के लिये है, आप प्रश्नकाल की बात उठायें ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, जो खड़े हैं उसको तो आप बोलिये ? इतनी शिष्टता तो होनी चाहिये ? अध्यक्ष जी, खड़े हैं उसको तो सुनिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये महत्वपूर्ण होता है । छत्तीसगढ़ में आज तक परम्परा नहीं है कि हम प्रश्नकाल को बाधित करें । मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद शून्यकाल में पूरा समय रहेगा। आपको पूरा पर्याप्त समय दूंगा, आप सारे विषय उठा सकते हैं । लता उसेण्डी जी, प्रश्न करें । (व्यवधान)

जिला कोंडागांव अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग से संबंधित स्वीकृत कार्य

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

1. (*क्र. 715) सुश्री लता उसेंडी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोंडागांव जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 से दिनांक 10 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत किन-किन कार्यों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई, स्वीकृत कार्य हेतु कब-कब निविदा आमंत्रित की गयी एवं निविदा/अनुबंधों हेतु नियम शर्तें क्या थीं ? प्रश्नअधीन अवधि में स्वीकृत कार्य हेतु किन-किन संस्थानों को कितनी राशि का भुगतान किया गया, क्या प्रश्नाधीन अवधि में स्वीकृत कार्यों में निविदा शर्तों के पालन नहीं करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां तो इस पर किस-किस संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई, वर्षवार जानकारी प्रदाय की जाए? **(ख)** वर्ष

[2] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

2021-22 एवं 2022- 23 के अंतर्गत एनएचएम द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु जारी निविदा में कितनी फर्मो ने निविदा में भाग लिया? किन किन फर्म का चयन कर आबंटित कार्य देकर कितनी कितनी राशि का भुगतान किया गया, जानकारी प्रदान करें । **(ग)** जिला अस्पताल, कोंडागांव अंतर्गत कितने पदों का सेटअप स्वीकृत हैं तथा स्वीकृति के अनुरूप कितने कर्मचारी, अधिकारी कार्यरत हैं तथा कितने पद, कब से खाली हैं, जानकारी देवें । **(घ)** क्या जिला हॉस्पिटल, कोंडागांव अंतर्गत रात्रिकालीन इमरजेंसी सेवाएं हेतु आवश्यक उपकरण एवं विशेषज्ञ चिकित्सक की उपलब्धता है तथा विगत 03 वर्षों में रात्रिकालीन समय में कितने प्रसव केस दर्ज हुए हैं तथा उसमें क्या कार्यवाही की गई, वर्ष वार जानकारी प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे **प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख)** वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के अंतर्गत एनएचएम द्वारा प्रिंटिंग कार्य हेतु जारी निविदा में 08 फर्मो ने निविदा में भाग लिया। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग)** जिला अस्पताल, कोंडागांव अंतर्गत 210 पदों का सेटअप स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदो के विरूद्ध 130 कार्यरत हैं एवं 80 पद रिक्त है। विगत तीन वर्ष से खाली है। **(घ)** जी हॉं। जानकारी **पुस्तकालय में रखें प्रपत्र "स" अनुसार।**

श्रीमती लता उसेण्डी :- मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या एन.एच.एम. के बारे में स्वास्थ्य विभाग को निविदा को लेकर कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिले में निविदा को लेकर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से जानकारी चाही थी..।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि निविदा को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । मेरे पास जानकारी है । जो शिकायत प्राप्त हुई है तो उस शिकायत के आधार पर माननीय मंत्री जी के ओएसडी द्वारा क्या संचालक महोदय को, अवर सचिव को कार्रवाई के लिए कोई पत्र लिखा गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के उत्तर में ही कहा है कि निविदा संबंधी शर्तों को पालन करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत हो तो वे मुझे दे देंगे, मैं उसको पृथक से नियमानुसार दिखवा लूंगा ।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 महीने हो गए, लगातार शिकायतें चल रही हैं और इस पर माननीय मंत्री जी के यहां से कोई पत्र गया है और 10 महीने हो गए हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । निविदा और वाहन को लेकर जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन वर्षों में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री जी विभागीय जांच कराएंगे या उन्हें निलंबित करेंगे ? जो भी

जवाबदार अधिकारी हैं, उस संबंध में मेरा प्रश्न है कि एनएचएम के द्वारा जो वाहन संचालित किया जाता है, वह विभागीय है या फिर टेण्डर के द्वारा कराया गया है ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एनएचएम से विभिन्न मदों से जो पैसा प्राप्त होता है, उसमें चिरायु योजना वाहन के लिए होता है। विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए निविदा के आधार पर ही वाहन को रखा गया है और इसी प्रकार से निविदा में गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जानकारी है, सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी ली गई है और शिकायत भी माननीय मंत्री जी के यहां की गई है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसमें सी.एम.एच.ओ., डी.पी.एम. और डी.एम.ओ. तीनों इसके लिए दोषी हैं । क्या तीनों अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई माननीय मंत्री जी करेंगे ? मेरे पास सारी चीजों की जानकारी है। फ्लैक्स की जो निविदा की गई है, उसका दर 7.90 रूपए है, जिसका भुगतान 17 रूपए कराया गया है, मेरे पास उसके बिल भी कॉपी भी रखी हुई है । विभागीय जांच कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- कार्रवाई करेंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इनके पास जो भी जानकारी है, वे मुझे दे देंगी तो मैं उसे नियमानुसार दिखवा लूंगा ।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें विभागीय जांच कराएंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप विभागीय जांच कराएंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास कोई तथ्य है तो मुझे दे देंगी ।

सुश्री लता उसेंडी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे तथ्य हैं । शिकायत के आधार पर विभागीय जांच कराएंगे क्या ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- ठीक है, उसकी जांच करा देंगे ।

सुश्री लता उसेंडी :- विभागीय जांच कराएंगे ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- नियमानुसार उसकी जांच करा देंगे ।

समय :-
11:29 बजे

गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्नलिखित सदस्य अपना स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत)
2. श्रीमती अनिला भेंडिया
3. श्री उमेश पटेल
4. श्री लखेश्वर बघेल
5. श्री दलेश्वर साहू
6. श्री भोलाराम साहू
7. श्री लालजीत सिंह राठिया
8. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े
9. श्री दिलीप लहरिया
10. श्री रामकुमार यादव
11. श्रीमती अम्बिका मरकाम
12. श्रीमती संगीता सिन्हा
13. श्री कुंवर सिंह निषाद
14. श्रीमती यशोदा नीलाम्बर वर्मा
15. श्री इंद्रशाह मण्डावी
16. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी
17. श्री विक्रम मण्डावी
18. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
19. श्री ब्यास कश्यप
20. श्रीमती शेषराज हरवंश
21. श्रीमती चातुरी नंद
22. श्रीमती कविता प्राण लहरे
23. श्री संदीप साहू
24. श्री इंद्र साव
25. श्री जनक ध्रुव
26. श्री ओंकार साहू
27. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि कृपया निलंबित सदस्य सदन के बाहर जाएं।

(कांग्रेस पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए सदन से बाहर गए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय

11.30 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)**

प्रश्न संख्या 02 : XX XX

समय

11.30 बजे **निलंबन समाप्ति की घोषणा**

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली 250 के उप नियम (1) के तहत जो माननीय सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गए थे, मैं उनका निलंबन समाप्त करता हूं।

समय

11.30 बजे **तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)**

सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले मेडिकल कॉलेज एवं मशीन व उपकरण का क्रय

[चिकित्सा शिक्षा]

3. (*क्र. 368) श्री विनायक गोयल : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में ऐसे कितने मेडिकल कॉलेज हैं, जो कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं? कृपया उनका नाम बताने का कष्ट करें? **(ख)** मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में विगत दो वर्षों में क्या-क्या मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण कितनी-कितनी राशि के क्रय किए गए? **(ग)** वर्तमान में प्रश्नांश **(ख)** अंतर्गत मशीनें चालू अवस्था में हैं या नहीं? **(घ)** क्या मशीनों एवं अन्य उपकरणों की खरीदी बिक्री में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) : (क) प्रदेश में कुल 04 मेडिकल कॉलेज सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसमें 1. स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर, 2. राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, 3. स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, 4. स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर हैं। **(ख)** स्व. श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, डिमरापाल जगदलपुर के द्वारा विगत दो वर्षों में मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण हेतु राशि 3,78,18,001=00 (रूपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख अठारह

हजार एक मात्र) की खरीदी की गई है। जानकारी प्रपत्र[3] अनुसार। **(ग)** वर्तमान में प्रश्नांश **(ख)** अंतर्गत खरीदी गई सभी मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण चालू हैं।**(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

श्री विनायक गोयल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने मेडिकल कालेज हैं, जो कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं? कृपया उनका नाम बताने का कष्ट करें? मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में विगत दो वर्षों में क्या-क्या मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण कितनी-कितनी राशि के क्रय किए गए? वर्तमान में प्रश्नांश अंतर्गत मशीनें चालू अवस्था में हैं या नहीं? क्या मशीनों एवं अन्य उपकरणों की खरीदी बिक्री में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को लिखित में इसकी जानकारी दिया हूं फिर भी बता देता हूं कि प्रदेश में कुल 04 मेडिकल कालेज हैं, जो कि अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित हैं। जिनमें स्व.श्री बलीराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जगदलपुर, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, स्व. बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा, स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर हैं। इसके अलावा अभी हमारे माननीय विष्णु देव जी की सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र में 02 और मेडिकल कालेज जिसमें से एक मनेन्द्रगढ़ में और एक कांकेर में भी स्वीकृत किए है, जिसे अभी आने वाले समय में संचालित करेंगे। इनके दूसरे प्रश्न में इन्होंने मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में दो वर्षों में मशीन खरीदी की जानकारी चाही है, तो दो वर्षों में मशीन/कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरण 3,89,58,025=20 (तीन करोड़ नवासी लाख अट्ठावन हजार पच्चीस रुपए बीस पैसे) की खरीदी की गई है, जिसकी जानकारी "प्रपत्र -अ" में उनको दी गई है और किसी भी मशीन और कम्प्यूटर की खरीदी में किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हे। सभी मशीनें और कम्प्यूटर संचालित हैं, इसलिए इनका जो "घ" नंबर का प्रश्न है, अनियमितता संबंधी कोई प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

श्री विनायक गोयल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज में वहॉ उपकरण तो हैं, मगर कुछ बंद पड़े हुए हैं। जैसे कम्प्यूटर्स हैं, एक्स-रे मशीन हैं, साथ ही सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि वह अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ?

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन कम्प्यूटर्स एवं उपकरणों की बात कर रहे हैं, मैंने कल भी और आज भी पूरी जानकारी ले ली है, कोई भी उपकरण और मशीनरी बंद नहीं है, सभी संचालित हैं। आप बीच में कुछ पहले गए होंगे तो खराब रहा होगा। मैं भी दौरे में गया था, तो उस सबको ठीक करने के लिए कहा गया था, परंतु आज की स्थिति में सभी चालू हैं

[3] परिशिष्ट "दो"

और जो सुपर स्पेशियालिटी हॉस्पिटल जगलदपुर है, उस पर हमारी भी चिन्ता है कि जल्दी से जल्दी कैसे चालू हो। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोग उसे जल्द ही चालू कर रहे हैं। उसके संचालन हेतु हमारे प्रदेश में डॉक्टरों, विशेषज्ञों की कमी होने की वजह से हमने उसके लिए टेण्डर अपलोड कर दिये हैं, जिसमें प्राईवेट सेक्टर के बड़े हॉस्पिटल भी आयेंगे। उसका संचालन राज्य सरकार ही करेगी। इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छा विषय यह है कि हमारे अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में जो डॉक्टर और प्रोफेसर हैं, वे उसमें नहीं जाते है। उसके लिए जो पहले की दर थी, हमने उसको लगभग 3 गुना से अधिक प्रस्तावित किया है और जल्द ही मुझे लगता है कि विशेषज्ञों की कमी दूर हो जायेगी। जैसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में प्राध्यापक को 90 हजार रूपये दिये जाते थे, उसको अब 3 लाख 30 हजार रूपये प्रस्तावित किया गया है और जो सह प्राध्यापक हैं, उनको 80 हजार रूपये के स्थान पर 2 लाख 80 हजार रूपये प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही सहायक प्राध्यापक सुपर स्पेशलिटी को जो 50 हजार रूपये के स्थान पर 1 लाख 80 हजार रूपये और सीनियर रेसीडेन्स को 40 हजार रूपये के स्थान पर 1 लाख 30 हजार रूपये देने का प्रस्ताव हमने वित्त विभाग को भेजा है। मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी और आने वाले समय में हम लोग जगदलपुर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जल्द ही चालू कर रहे हैं।

श्री विनायक गोयल :- अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं, मैं चाहता हूं कि वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। जैसे, वार्ड ब्वाय, स्वीपर, आया और साथ ही में वहां की जो नर्सें हैं, जिन्होंने कोचिंग की है, उनको वहां रोजगार देना चाहिए। वहां के स्थानीय लोग बेरोजगार हैं। ऐसे लोगों को एक रोजगार मिलना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस शासन में स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर स्वर्गीय महेन्द्र कर्मा मेडिकल कॉलेज रख दिया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम पुन: स्व. बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज किया जाये।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्थानीय लोगों के रोजगार से संबंधी चिंता व्यक्त की है। इस विषय में जब मेरा जगदलपुर दौरा था, तब वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरी बातचीत भी हुई थी। परंतु हम शासन के नियमानुसार जो ठेका देते हैं, वह प्लेसमेंट एजेंसियों को देते हैं और उनकी नियम व शर्तों को पूरा करने वालों को नौकरी दी जाती है। मैंने उन्हें कहा है कि वे वहां के स्थानीय लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दे, तब यदि वे सभी शर्तों को पूरा करेंगे तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हम वहां पर स्थानीय लोगों को ठेका भी दे और यदि बाहर के लोग ठेका लेते भी है तो हमारा यह पूरा प्रयास होगा कि जो वहां के स्थानीय लोग हैं और योग्यता धारक हैं, उनको उन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाये, जिससे वहां सुचारू रूप से काम भी हो सकेगा। दूसरा, अभी माननीय सदस्य ने जो नाम परिवर्तन की बात की है। मैं उसको एक बार दिखवा लूंगा कि यदि नाम को बदला

गया है तो उसके क्या कारण है। हम एक बार बैठकर हमारी समिति के माध्यम से उसका परीक्षण करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। श्री धरमलाल कौशिक जी के स्थान पर श्री अजय चन्द्राकर जी को अधिकृत किया गया है।

डिजिटल अरेस्ट/साईबर क्राईम प्रकरणों पर कृत कार्यवाही

[गृह]

4. (*क्र. 507) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 अंतर्गत प्रदेश में जिलावार कुल कितने-कितने डिजिटल एरेस्ट/साईबर क्राईम के माध्यम से राशि हड़पने के प्रकरण दर्ज हुए हैं? इनमें से कितने पीड़ितों से कितनी राशि अवैध रूप से वसूली गई है और कितनी राशि पीड़ितों को वापस कराई गई है और कितनी वापस होना बाकी है? जिलावार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका (क) अंतर्गत अवधि में से कितने आरोपी चिन्हांकित किये गए हैं ? कितने गिरफ्तार किये गए हैं तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है व कब तक गिरफ्तार किये जावेंगे? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार अपराध हेतु कुल कितने खातों में अवैध रूप से राशि स्थानांतरित कराई गई है तथा इनमें से कितने खाते अभी बंद हो गए हैं और कितने खाते अभी भी चालू हैं और इन्हें अभी तक बंद क्यों नहीं कराया गया है? कितने खातों को बंद कराने का अनुरोध करने के बाद भी दिनांक 31.01.2025 तक बैंक प्रबंधन द्वारा खाते बंद नहीं कराये गए ? इनमें से कितने खाते ऐसे हैं, जिनमें 2 या अधिक पीड़ितों की राशि उनमें से एक ही खाते में अलग-अलग समय में हस्तांतरित की गयी है ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) प्रश्नाधीन अवधि की जिलावार जानकारी पुस्तकालय में रखे **प्रपत्र - "अ"** अनुसार है। **(ख)** जानकारी पुस्तकालय में रखे **प्रपत्र - "ब"** अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे **प्रपत्र- "स"** अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न के पहले ईशारा करना ठीक नहीं है। आप प्रश्न करिये और उसकी गंभीरता को बनाये रखिये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई ईशारा नहीं किया है। में माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो साईबर क्राइम हुए हैं, उसमें डिजिटल अरेस्ट की कितनी घटनाएं हुई हैं और आपने उसमें कितने प्रकरणों में कार्रवाई की है ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, साईबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के कुल प्रकरणों में से छत्तीसगढ़ में डिजिटल अरेस्ट के 12 प्रकरण हैं। इन सभी प्रकरणों में कार्रवाई भी की गयी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी दी है, उसके अनुसार साइबर ठगों ने लगभग 168.82 करोड़ रूपये की ठगी की है। उसमें से आपने ठगों से कितनी राशि वसूल की है ? आपने कितनी राशि ठगे गये लोगों को वापस की है और शासन या विभाग के पास कितनी राशि रखी हुई है? आप उसको कब तक उनको लौटाएंगे?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिजिटल एरेस्ट/साईबर क्राईम के कुल प्रकरणों में से 168 करोड़ रूपये ठग लिये गये। उसमें से 5 करोड़ 20 लाख रूपये वापस दिलाये गये हैं। जो हमारे ओल्ड एकाउंटस हैं जिन एकाउंट्स में राशि होल्ड की गई है यह 4427 एकाउंट्स हैं, जिनको होल्ड किया गया है। इन होल्ड एकाउंट में 4 करोड़...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री महोदय, उन होल्ड एकाउंट्स की बात नहीं है। मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा था कि इन प्रकरणों में 168 करोड़ रूपये की ठगी हुई। आपने 5 करोड़ रूपये वसूल किया है या उससे ज्यादा राशि वसूल की है। यदि आपने ज्यादा राशि वसूल की है तो उनको केवल 5 करोड़ 20 लाख रूपये ही वापस किया है। यदि आपके विभाग के पास ज्यादा राशि है तो आप उसको कब वापस करने जा रहे हैं ? और इन प्रकरणों में बाकी वसूली के लिए आपकी क्या कार्यवाही चल रही है ? मैंने यह प्रश्न पूछा है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रकरणों में 5 करोड़ 20 लाख रूपये पीड़ितों को वापस किया गया है। मतलब 4400, जितने खाते होल्ड किये गये हैं उसमें 4 करोड़ 13 लाख की राशि है जिसमें परीक्षण और अंतिम निर्णय के उपरांत उसको भी दिया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रकरणों में ठगी के बाद अभी भी चालू बैंक खाते 1795 है, जो आपने परिशिष्ट में जानकारी दी है। उसके बाद उसमें 921 खाते ऐसे हैं, जिनमें एक से अधिक बार ट्रांजेक्शन हुए हैं और इन प्रकरणों में ठगी की घटना 921 खातों में एक से ज्यादा बार हुई है। अभी तक इन खातों को फ्रीज नहीं किया गया और अभी तक यह खाते चालू हैं इन खातों को जारी रखने के पीछे विभाग की क्या मंशा है ? या किन कारणों से इन खातों को चालू रखा गया है, यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब जब हम साईबर फ्रॉड की दिशा में जांच होती है तो इसमें अनेक लेयर में ट्रांजेक्शन आगे बढ़ जाता है। वह राशि एक खाते से दूसरे खाते और उसके बाद तीसरे खाते में जाती है। जहां पहले खाते में राशि जाती है अनिवार्यत: उसको बंद कर लिया जाता है और उसके बाद के खातों में हो सकता है कि उसने कहीं खरीदी की है और वहां खरीदी के बाद भुगतान कर दिया है तो हमें मर्चेन्ट का खाता पता चला तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है। उस

ट्रांजेक्शन को फ्रीज करके, खाता फ्रीज नहीं किया जाता है, उसमें यह स्थिति अपनाई जाती है इसलिए मैंने माननीय सदस्य महोदय जी से जिस स्थिति के बारे में कहा कि इन प्रकरणों में जितने खाते बंद नहीं किये गये हैं, उन हर खातों के पीछे ऐसी कोई न कोई विषय है। इसलिए मैं यह बोल रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इन प्रकरणों में 921 खातें ऐसे हैं, जिनमें एक से दो बार साईबर क्राईम द्वारा ठगी हुई। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि अभी भी वह खाते चालू है। यदि आप कुछ बोल रहे हैं तो अपनी बात बोल लीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 921 खाते ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक बार ट्रांजेक्शन हुआ है, यह खाते चालू है ऐसी बात नहीं है। इन खातों में एक से अधिक बार ट्रांजेक्शन हुआ है। इसमें एक से अधिक बार राशि ट्रांसफर हुई है। वह खाता बंद भी हो गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा, वह खाता बंद हो गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे-छोटे दो विषय हैं। आपने इन प्रकरणों में कुल 722 लोगों को चिन्हित किया है आपने 722 लोगों में से 347 की गिरफ्तारी की है। इसमें बाकी लोगों की गिरफ्तारी या बाकी जांच में तेजी आए, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ। पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण लगा था। इस सदन में यह पहली बार बहस में आ रहा है। यह प्रदेश की बड़ी समस्या है। इसमें बाकी लोगों के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं ? इसमें दूसरा विषय यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के पास साईबर क्राईम के लिए क्या-क्या विशेषज्ञताएं हैं कि इन मामले का शीघ्रता से निराकरण हो। आप उनकी थोड़ी विशेषज्ञताएं भी बताएंगे ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह चिन्ता वस्तुत: वर्तमान में जो समाज की चिन्ता है, वही है। संपूर्ण भारत वरन् संपूर्ण विश्व की सुरक्षा भी साईबर सुरक्षा के बिना अब संभव नहीं है । हम भारत में ही देखेंगे तो 2024 में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का digital transaction हुआ है और यह पूरी दुनिया का 40 प्रतिशत से अधिक है। लोकसभा का एक विषय टी.व्ही. पर देखा था। पी. चिदम्बरम जी कहते थे कि- go to a village house by potatoes and tomatoes and pay rupees 750 using a credit card what will a poor woman do in such a situation with there it we are an ATM machine, there we an electricity, there we wifi, there we internet. यह चिदंबरम जी ने उस समय भाषण दिया था जब डिजिटल इंडिया का कांसेप्ट लेकर के माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आगे बढ़ी थी। उसके बाद आज जो हमारा भीम एप, गेट गेटवे, यू.पी.आई है, यह जर्मनी और फ्रांस में भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। हम digital transaction की दिशा में बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि एक गांव में एक महिला आलू बेच रही है और उसके पास जब एक व्यक्ति खरीदने जाता है तो वह digital transaction से ही भुगतान कर रहा है, भारत digital transaction में इतना आगे बढ़ा है। इसलिए जब यह digital transaction की तरफ हम

जाते हैं तो साईबर अपराध भी भारत में बढ़े हुए दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में बढ़े हैं और भारत में भी बढ़े हैं। यह जो 722 आरोपी वर्तमान में चिन्हांकित हैं, यह पूरे नही हैं। मैं माननीय सदस्य महोदय की चिंता के आधार पर उनसे कहना चाहूंगा कि यह 722 आरोपी अभी तक चिन्हांकित हुए हैं। इसमे तो और आरोपी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने जो परिशिष्ट दिया है, मैं उसी के अंदर ही प्रश्न कर रहा हूं। परिशिष्ट के बाहर आपके पास जानकारी होगी।

श्री विजय शर्मा :- मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात तो एक मिनट सुन लीजिए। यह जो 722 आरोपी हैं, यह अब तक चिन्हांकित हुए हैं, उसमें से 375 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं, अन्य की गिरफ्तारी की, खोज की प्रक्रिया अभी जारी है। अब इसमें जीओ स्पेशल बाउंड्रीस नहीं हैं। इसमें प्रदेश की पुलिस भी पूरा नहीं कर सकती है इसलिए भारत सरकार में यू.एच.एम. और हमारे सेन्ट्रल की होम मिनिस्ट्री ने इस पर बहुत बड़ा अभियान किया है। दुनिया का सबसे अच्छा अभियान अगर साईबर क्राईम के लिए कहीं किया जा रहा है तो वह भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे प्रश्न का एक पार्ट बच गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इसकी विशेषज्ञता क्या है? आपने इसके लिए क्या प्रयास किये हैं? भारत सरकार जो कर रही है, कर रही है, आप उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैंने बाकी को पकड़ने के लिए पूछा, आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे convence हूं। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के पास इन घटनाओं के बाद खुद की क्या विशेषज्ञता है? दूसरा क्या इसी सदन में साईबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी? और यदि हुई थी तो कितने साईबर थाने खोले गये?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो केन्द्र की बात कही वह इसलिए कही कि क्योंकि साईबर अपराध खाली राज्य का विषय नहीं है और राज्य तक सीमित नहीं होता है। यह राज्य के अंदर कहीं एक स्थान पर होने वाली घटना नहीं होती है। इसका आरोपी कहीं दूर दूसरे प्रदेश में बैठा होता है। इसलिए पूरे देश के संदर्भ में सोचना और यहां तक कि पूरे विश्व को मिलाकर एक साथ सोचने की इसमें आवश्यकता है। मैं वह बता रहा था। माननीय सदस्य महोदय का जो कहना है, मैं स्पेसीफिक विषय पर आ जाता हूं। राज्य में नई सरकार बनने के बाद एक साईबर भवन का निर्माण कराया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ 77 लाख की लागत से भवन तैयार कराकर 4 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया। उसमें जितने पुराने लाईसेंस नवीनीकरण बचे थे, 1 करोड़ 46 लाख में वह किये गये। फिर 51 लाख रुपये के नये सॉफ्टवेयर आदि खरीदे गये। उन सॉफ्टवेयर में भी विशेषज्ञता के लिए आप कहेंगे तो सारे equipments जो हमारे पास उपलब्ध हैं, Unified forensic extension divices वहां पर है, XRY mobile forensic kit वहां पर है। वहां पर Magnet Axion compete disk storage के detection के लिये है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूं। भवन बनाकर equipments की बात आप बता रहे हैं। जो मेरी जानकारी है जब equipment का संचालन करना, देखना और उसके एक्सपर्ट होंगे, तब इन सारे संसाधनों का उपयोग होगा, जिसकी आप गिनती कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता कि विशेषज्ञता में आपने equipments जुटा लिये, बहुत बढ़िया। विभिन्न समाचार पत्रों में सब में यह छपा है कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह के साईबर विशेषज्ञ नहीं हैं। यह बात आप बतायेंगे कि ये सत्य है या असत्य है ? मैं समाचार पत्र में छपने पर नहीं जा रहा हूं सिर्फ उसका उल्लेख कर रहा हूं। तो मशीन-भवन एक अलग चीज है, उसको ऑपरेट करने के लिए विशेषज्ञता एक दूसरा विषय है और दूसरी बात जो मैंने कही कि क्या cyber थाने खोलने की घोषणा इस सदन में हुई थी ? कितने थाने खोलने की घोषणा हुई थी और कितने खुले ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर cyber police थाना, राज्य स्तर पर cyber forensic lab, cyber financial fraud helpline जो 1930 है, वह राष्ट्रीय स्तर का है परंतु उसका संचालन सभी राज्यों को स्वयं करना पड़ता है वह भी यहां पर संचालित किया जा रहा है । हमारे जो 5 रेंज हैं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर इन 5 रेजों में थाना को और upgrade किया गया है और आगे बढ़ाया गया है । उसमें specifically Cyber थाने हैं और समस्त जिलों में सभी एक-एक cyber cell का भी निर्माण हुआ है । यह सब मिलकर के यह संस्था काम कर रही है और दूसरा जो आपसे मैं यह कहना चाह रहा था कि आगे भी इस विषय को ले जाने के लिए जो staff वहां पर नियुक्त है, cyber crime के लिए specifically कोई नियुक्ति होती है, ऐसा नहीं है । जो हमारे लोग हैं उसमें से ही हो रहा है । माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक concept दिया कि हमको 5 हजार cyber commandos बनाने हैं तो उसमें अभी 6 लोग commando की training ले रहे हैं, वह भी एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है । छः महीने की एक बड़ी national level की एक training होती है, Triple IT हमारा नया रायपुर वहां पर भी एक training center है तो वह training ले रहे हैं । इसके साथ ही साथ अभी हमने 5 experts को इंगेज करने की प्रक्रिया बढ़ाई है और जो हमारे लोग यहां पर पहले से उपस्थित हैं जिनको अन्य training I four C के माध्यम से दी गई है वह सब इसमें कार्यरत हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक आख़िरी प्रश्न पूछ लेता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के प्रश्न से जो समझा है कि आपकी विशेषज्ञता को जो मैं पूछ रहा था तो आपने कहा कि commando training ले रहे हैं, national grid में उनकी training हो रही है और कुछ जगह आप खुद भी कर रहे हैं । अभी एक और उत्तर आ रहा था कि हमने विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्त विभाग में भेजा है । मैंने specific पूछा है कि आज की तारीख में जितनी घटनाएं हुई हैं, जितने पैसे की ठगी हुई है इन सबकी जांच-पड़ताल समय में हो । अपने पास इस-इस

तरह के इतने विशेषज्ञ हैं या इतने विशेषज्ञों की ज़रूरत है और इतने विशेषज्ञों की हम भर्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता था, एक ? दूसरा, मेरी जानकारी यह है कि इस सदन में पांचों जो आपके रेंज हैं उसमें 5 साइबर थाने खोलने की घोषणा हुई थी । अब यह साइबर थाने का concept क्या है ? तत्कालीन गृहमंत्री या वह लोग जानें कि क्या concept है, मैं तो जाऊंगा नहीं और उसमें एक जगह शायद खोले गए हैं जिसमें भी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, जो मेरी जानकारी है तो जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वह यह है कि इन चीज़ों के निपटने के लिए इस तरह के विशेषज्ञ की ज़रूरत है, training वगैरह तो ठीक है, दिल्ली सरकार दे रही है, आप करवाइए । अच्छी बात है लेकिन हमारी जो विशेषज्ञता की ज़रूरत है और हमारे पास इतने हैं इस तरह के लोग और इतनी हम भर्ती करने जा रहे हैं, मैं यह specific जानना चाहता था और आप specific cyber थाने के बारे में बताइए, cyber cell के बारे में नहीं ? cyber थाने खोलने की बात कही थी कि cyber cell खोलने की बात कही थी ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं और बिल्कुल स्पष्टता से specifically मैंने वही बात कही कि इसमें cyber crime के लिए अलग से कोई नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है । जो लोग उपस्थित हैं उन्हीं से होना है और इसलिए मैं आपको फिर से एक-बार बताना चाहता हूं कि 5 रेंज में cyber थाने हैं और उसमें 69 लोग कार्यरत हैं । यह पूर्व से police विभाग में कार्यरत लोग ही हैं जो उस दिशा में expert हो सकते हैं उनको रखा गया है । मैंने इसी में बताया कि अभी recent में भी और दो साल पूर्व भी । four c जब से प्रारंभ हुआ है, वर्ष 2022 से । four c प्रारंभ हो जाने के बाद यह भारत सरकार की बड़ी संस्था है और यह भारत सरकार का बड़ा अभियान है । सारी चीज़ों को एक-साथ इंटीग्रेट करने के लिए Indian cyber crime coordination center (I four C) ऐसा बनाया गया है । इसी के माध्यम से प्रशिक्षण एक छोटे कालखंड का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । छत्तीसगढ़ में 129 लोग प्रशिक्षित हुए और वह कार्यरत हैं । बाकी 5 रेंजों में 5 cyber थाने हैं और उसमें 69 लोग कार्यरत हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 5 विशेषज्ञों की नियुक्ति का जो विषय है, वह attach किए जाएंगे । उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं होगी, वह attach किए जाएंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जो 5 लोगों की recovery हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा । नहीं, बस हो गया । प्रश्न क्रमांक-5, श्रीमती भावना बोहरा जी । यह समाप्त हो गया, भावना जी पूछिए ।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्रान्तिर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़को हेतु जारी निविदायें

[पंचायत एवं ग्रामीण विकास]

5. (*क्र. 677) श्रीमती भावना बोहरा : क्या उप मुख्यमंत्री (गृह) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कौन-कौन सी और कितनी सड़कें आती हैं ?उनकी कुल लंबाई कितनी है ? (ख) वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक इनमें से कितनी सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है ? टेंडर जारी करने पश्चात कितने सड़कों का कार्य पूर्ण किया गया है एवं कितनी सड़कों का निर्माण जारी है ? (ग) शेष सड़कों हेतु कब तक टेंडर जारी किए जाएंगे ?

उप मुख्यमंत्री (गृह) (श्री विजय शर्मा) : (क) जानकारी संलग्न [4]"प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) वर्ष 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक उक्त सड़कों में से 04 सड़कों हेतु टेंडर जारी किया गया है। टेंडर जारी करने पश्चात पूर्ण कार्यों की संख्या निरंक है एवं 04 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगतिरत् है। (ग) टेंडर जारी किये जाने हेतु शेष सड़कों की संख्या निरंक है।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । संयोग ऐसा है कि मुझे आखिरी के 5 मिनट ही मिलते हैं तो मैं मुख्य प्रश्न में ही आना चाहूंगी । जब से सत्र शुरू हुआ है तब से प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग जो 50 सड़कें हमारे क्षेत्र में आती हैं, उसमें से 37 सड़कों की स्थिति बहुत ही ज्यादा जर्जर है और पूरी पंडरिया विधानसभा की स्थिति लगभग यही है। मैं मंत्री जी को इसमें एक जानकारी देना चाहूंगी, हालांकि उनको इस विषय में ज्ञात होगा कि विभाग से पिछले एक वर्ष में चार बार विभागीय प्रस्ताव आ चुका है कि इन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है। सड़कों के निर्माण की जरूरत है, जो जनवरी, 2024, जुलाई, 2024, नवंबर, 2024 और जनवरी में 2025 में चार बार विभाग से प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन 37 में से सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति अभी अंतिम जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिली है तो मैं पूछना यही चाहूंगी कि विभाग इसको लेकर कितना गंभीर है? अगर किसी विषय पर विभागीय जानकारी लगातार क्रमश: 4 बार आ रही है तो मुझे लगता है कि यहां जो हमारे मंत्री जी के विभाग से जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, कम से कम उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि लगातार जो विषय आ रहा है तो निश्चित ही वह गंभीर होगा। तो मेरा प्रश्न बस ये है कि चार बार आने के बाद भी इस विषय पर गंभीरता क्यों नहीं ली गई? 37 सड़कों में अगर स्वीकृति हुई तो सिर्फ 4 सड़कों की स्वीकृति क्यों हुई है और बाकी सड़कों की स्वीकृति की क्या स्थिति है और वह कब तक हो पाएगी?

---

[4] परिशिष्ट "तीन"

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समूचे प्रदेश में ही 56 सड़कें स्वीकृत हैं। 56 सड़कों में से 4 सड़कें माननीय सदस्य महोदया के विधान सभा क्षेत्र पंडरिया में स्वीकृत हैं और बाकी पूरे प्रदेश में जो शेष 56 सड़कें हैं और उसमें विशेष रूप से वित्त के जो प्रावधान हैं, वित्त की जो अनुमति है, स्वीकृति है, प्राप्ति है, उसके आधार पर उसको होना है। तो निर्णय यह है कि आपके माध्यम से भेजे गए प्रत्येक पत्र मेरे हाथ में हैं और इन सारे पत्रों को प्रावधानित करके वित्त विभाग में भी भेजा हुआ है। इसका अंतिम निर्णय जब हो जाएगा..।

श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जब विषय आता है, वित्त विभाग से बात करें तो उनका ये कहना रहता है कि जो संबंधित विभाग है वहां से हमारे पास लेटर फॉरवर्ड नहीं हुआ है। फाइल फॉरवर्ड नहीं हुई है तो confusion ये हो जाता है कि हमें वित्त विभाग में कब जाना है और जहां पर हमने अपनी फाइल दी है, जो उसका प्रथम चरण विभाग है, वहां पर तो दोनों में तालमेल नहीं होने से हमको काम में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। यही स्थिति सिर्फ नए निर्माण सड़कों की नहीं हैं, जो सड़कें जर्जर हो गई हैं, जिनकी संख्या लगभग 35 के आसपास है, जिनके मरम्मत को 5 साल से ऊपर हो गया है, उनके भी कई बार प्रस्ताव, आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन सड़कों की मरम्मत 5 साल पूरे होने के बाद भी नहीं हुई है और स्थिति यह है कि बारिश के मौसम में जो गाड़ियां गन्ने की निकलती हैं, कई बार ट्रैक्टर एवं बहुत सारी गाड़ियां पलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं तो कृपया संज्ञान में लेकर यह जरूर एक बार मुझे जानकारी अगर हो पाए तो दे पाएं कि कब तक ये चीजें आगे हो पाएंगी, क्योंकि सड़कों की संख्या भी काफी ज्यादा है और सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय सदस्य महोदया की चिंता है और उसके लिए 10 करोड़ रूपये का प्रावधान भी बजट में था और उसमें से 6 सड़कें भी पंडरिया विधानसभा की ली गई हैं और उन 6 सड़कों पर काम, मैं सोचता हूं कि शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा। शेष जितनी भी सड़कें हैं, उन सबको प्रावधानित कर उसका निर्णय भी किया गया है। वह अपने 10 करोड़ के प्रावधान के अंदर-अंदर है। पेंच रिपेयरिंग के अतिरिक्त इसमें जो अन्य कार्य हैं, जिसमें नवीनीकरण या सुदृढ़ीकरण है, उसके अपने-अपने मानक हैं। उसके जो भी सारे प्रस्ताव हैं, वे विभाग को पहुंचे हैं। विभाग को भेजे हुए प्रस्ताव की प्रति भी मैं माननीय सदस्य महोदया को उपलब्ध करा देता हूं।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि किस किस टाइप की सड़कों को प्राथमिकता देंगे? क्योंकि चार बार आवेदन ऑलरेडी आ गया है तो अगली बार क्या मुझे फिर से विभाग से प्रस्ताव भेजना पड़ेगा तब वह स्वीकृत होगा? क्या प्रक्रिया है? उसमें थोड़ा सा संज्ञान डालें और दूसरा एक छोटा सा सवाल है। इसमें कुमही से कोलारीकापा सड़क, जिसका आधा निर्माण हुआ है और मुझे लगता है कि 500 मीटर की सड़क 300 मीटर निर्माण हो करके कार्य बंद कर दिया गया है

और इसमें लिखा गया है कि यथास्थिति अनुबंध समाप्त। तो इसकी स्थिति क्या है? जिस स्थिति में अभी तक वह सड़क छोड़ा गया है, आगे भी वैसा ही रहेगा या उसमें आगे कोई स्वीकृति अलग से मिलने वाली है?

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुमही से कोलारीकापा जो सड़क है, ये पर्यावरण एवं अधोसंरचना मद के अंतर्गत बन रहा था, उसके लिए जी.एस.बी. स्तर तक कार्य पूर्ण होने के बाद राशि आगे नहीं हुई और जब वह राशि नहीं हुई, इसलिए उसे उस स्थिति में..।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, समय कम है, बस यही निवेदन करूंगी कि इस बार स्वीकृति मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कृपया, मंत्री जी एक बार बता दें कि मुझे कितनी सड़कों की स्वीकृति मिल सकती है? क्योंकि वे खुद भी उसी क्षेत्र के हैं और सारी स्थिति से अवगत हैं कि वहां पर सड़कों की कैसी स्थिति है। तो बस यही जानना चाहूंगी कि कब तक हो पाएगा, कितना मैक्सिमम हो पाएगा? कृपया उसे संज्ञान में डाल दें।

श्री विजय शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं सिर्फ कह सकता हूं कि जस हाल ऊधो तस हाल माधो है। इसमें कोई अंतर नहीं है । सब कुछ मिला-जुला सा बिल्कुल वही है । यहां पर चूंकि पर्यावरण अधोसंरचना मद से राशि नहीं मिली, इसलिए कुमही- कोलारीकापा को वहीं स्थगित किया गया। कोशिश करेंगे कि इसको अन्य मद से आगे कार्य को कराया जा सके और शेष तो ये है कि प्रावधान के आधार पर जो बजट में प्रावधान होगा, उसके आधार पर काम होगा।

श्रीमती भावना बोहरा :- महोदय जी, बस एक आखिरी निवेदन है। ये बता दें कि कौन से विभाग में फाइल आती जाती हैं, उसमें हमको बहुत confusion है कि हम वित्त विभाग जाएं या जिस विभाग में दिया, हमको एक बार वह क्लियर हो जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय

12.00 बजे **जन्मदिवस की बधाई**

श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सदस्य

अध्यक्ष महोदय :- सदन की सदस्या, माननीय श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा का जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से सदन की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें (मेजो की थपथपाहट) ।

विलोपन

सभा में उल्लेखित केन्द्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित अंश

अध्यक्ष महोदय :- केन्द्र शासन की एजेंसियों एवं उनके द्वारा सम्पादित कार्य नियमानुसार सभा में चर्चा का विषय नहीं हैं । अत: मैं सभा में केन्द्र सरकार की एजेंसियों से संबंधित उल्लेखित अंशों को कार्यवाही से विलोपित करते हुए प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सभा में अभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है । कृपया, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सार्थक चर्चा हेतु सभा की कार्यवाही में भाग लें ।

समय

12.01 बजे **अध्यक्षीय व्यवस्था**

प्रश्नों का स्वरूप नियमानुसार एवं संक्षिप्त हो, जिससे कि वे ग्राह्य किये जा सकें ।

अध्यक्ष महोदय :- वर्तमान सत्र में कुछ प्रश्नों द्वारा अपेक्षित जानकारी इतनी वृहद् है कि उसे विभाग के उत्तर में प्राप्त पृष्ठों की संख्या लगभग 10 हजार से अधिक है । शासन को ऐसे प्रश्नों का उत्तर तैयार करने में अत्यधिक समय एवं श्रम व्यय होता है । अत: माननीय सदस्यों से अनुरोध है अत्यंत विस्तारित स्वरूप में प्रदेशव्यापी या कई जिलों एवं अनेक वर्षों की से अपेक्षित जानकारीयुक्त प्रश्नों के स्थान पर कृपया प्रश्नों की ग्राहयता के संबंध में नियमों के अंतर्गत ही प्रश्नों की सूचना दें ताकि आपके प्रश्न ग्राहय हो सकें ।

समय

12.02 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-2025

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं ।

समय

12.02 बजे **ध्यानाकर्षण सूचना**

(1) विधान सभा क्षेत्र धरसींवा के ग्राम मढ़ी में गौरी गणेश कंपनी द्वारा मुख्य द्वारा का निर्माण आबादी क्षेत्र में किया जाना.

श्री अनुज शर्मा (धरसींवा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है:- विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के ग्राम मढ़ी में गौरी गणेश कंपनी का निर्माण चल रहा है। उक्त कंपनी द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण आबादी क्षेत्र में शासकीय स्कूल के पास किया गया है। कंपनी की बड़ी-बड़ी मालवाहक गाड़ियां बेतरतीब ढंग से मुख्य द्वार से लगे स्कूल के पास खड़ी रहती हैं साथ ही गाड़ियों के दिनभर आवाजाही से अध्यापन कार्य प्रभावित होता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है जिसके कारण स्कूली बच्चों का भविष्य अंधकारमय है एवं ग्रामीणजन धूल/प्रदूषण/दुर्घटनाओं से हमेशा दहशत में रहते है। कंपनी से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दर्शनीय स्थान में से एक माँ बंजारी धाम है। जहां रोज हजारों श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है। कंपनी के काले जहरीली धुंओं, गंदे केमिकलयुक्त पानी के प्रदूषण से होने वाली बीमारियों/परेशानियों के संबंध में स्थानीयजन पहले भी कई बार इस उद्योग स्थापना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इस उद्योग स्थापना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- यह कहना सही है कि गौरी गणेश इस्पात प्रा.लि. ग्राम-मढ़ी, विकासखण्ड-तिल्दा, विधानसभा क्षेत्र धरसीवा में निर्माणाधीन है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर के निरीक्षण दिनांक 22.02.2025 अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला-मढ़ी से इकाई के बाउण्ड्रीवाल की दूरी लगभग 200 मीटर है तथा संयंत्र की दूरी लगभग 500 मीटर है।

पूर्व में मुख्य द्वार निर्माण पर ग्राम सभा की आपत्ति के संबंध में राजस्व निरीक्षक मण्डल बंगोली द्वारा दिनांक 19.02.2024 को हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। ग्रामवासियों के कहने पर संयंत्र के पूरे भाग के लंबाई एवं चौड़ाई को नापकर बताया गया, जिससे

यह निष्कर्ष निकला कि संयंत्र द्वारा मुख्य द्वार भूमिस्वामी हक की भूमि पर बनाया जा रहा है। भाला का गेट दूसरी दिशा में है, जो इस निर्माण से बाधित नहीं हो रहा है। तहसीलदार खरोरा के द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण खारिज करने का आदेश पारित किया गया है।
अतः यह कहना सही नहीं है कि गाड़ियों की आवाजाही से स्कूल का अध्यापन कार्य प्रभावित होता है।

उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई दिनांक 30.03.2022 को ग्राम-मढ़ी में सरकारी खुला भाठा (शामिलात चारागाह) खसरा नंबर-07, हल्का पटवारी नंबर-35, राजस्व निरीक्षक मण्डल- बंगोली, तहसील-खरोरा (पूर्व तहसील-तिल्दा), जिला रायपुर (छ.ग.) में आयोजित की गई थी। तत्पश्चात् भारत शासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इकाई स्थापना सम्मति दिनांक 10.02.2023 जारी किया गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा दिनांक 11.10.2023 को स्थापना सम्मति (सी.टी.ई.) तथा संचालन सम्मति (सी.टी.ओ.) दिनांक 06.01.2025 को जारी किया गया है। इकाई के स्पंज आयरन प्रभाग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी.79 मीटर की चिमनी में स्थापित किया गया है तथा पावर प्लांट में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ई.एस.पी. 42 मीटर की चिमनी में स्थापित किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर टैंकरों के माध्यम से जल छिड़काव की व्यवस्था की गई है। उद्योग द्वारा 23 एकड़ भूमि में लगभग 15000 नग वृक्षारोपण किया गया है। दूषित जल के उपचार हेतु वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है।

डी. आर. आई. किल्न क्रमांक 1 का ट्रायल किया गया है। वर्तमान में उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा आज पर्यन्त इकाई को कोई वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

उद्योग द्वारा काली, जहरीली धुआ, गंदे केमिकल युक्त पानी से बीमारी के निराकरण हेतु इकाई द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उपाय किये गये हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, आवास एवं पर्यावरण विभाग के निरीक्षण दिनांक 22.02.2025 को उद्योग में जल एवं वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं पाई गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई। ग्राम पंचायत मढ़ी द्वारा इकाई स्थापना हेतु दिनांक 24.11.2021 को अनापत्ति प्रदान की गई है। अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व विभाग तिल्दा-नेवरा के प्रतिवेदन दिनांक 24.02.2025 अनुसार उद्योग स्थापना से कानून व्यवस्था अव्यवस्थित होने संबंधी किसी प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। भीड़ की स्थिति निर्मित होने पर नियंत्रित करने के लिये पुलिस प्रशासन के द्वारा समन्वय स्थापित कर कानून व्यवस्था स्थापित किया जाता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि उद्योग स्थापना को लेकर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीच अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एकदम प्वाईंटेड प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या उस फैक्ट्री के गेट का निर्माण उसी स्थान पर, उसी हिसाब से किया गया है जो अप्रूव्ड प्लान था ? मैं बस यही जानना चाह रहा हूं।

श्री लखन लाल देवांगन :- बिल्कुल, उसका जो परमिशन हुआ है, उसी के हिसाब से गेट की स्थापना हुई है।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप मुझे इस संबंध में जानकारी दे देंगे क्योंकि इसमें गांव वालों का ऐसा नहीं कहना है। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य मार्ग है, उससे जो फैक्ट्री की सड़क जोड़ी गई है, वह किसकी जमीन है, यह मंत्री जी थोड़ा स्पष्ट कर देंगे।

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, मैंने उस जमीन के बारे में जानकारी नहीं ली है, आप पूछ रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि जब जन सुनवाई में जिन बातों का विरोध किया गया था तो जन सुनवाई इसलिए की जाती है कि वहां जन भावना के हिसाब से अगर कोई परिवर्तन करना है तो कर ली जाए। क्या वहां जन सुनवाई के बाद जन भावना को देखते हुए उस पर कोई परिवर्तन किया गया था?

श्री लखन लाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, वहां ग्राम सभा हुई थी और वहां ग्रामवासियों के साथ जाकर उसका निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के बाद उसका पूरा निराकरण हुआ, तब उसको सारे विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। इसी तरह से उद्योग के द्वारा कोई भी अनियमितता नहीं बरती जा रही है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की अनियमितता हुई है तो आप हमें उसकी जानकारी दे दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य मार्ग से उस फैक्ट्री के गेट को जोड़ने वाली सड़क गांव के चारागाह की जमीन पर बनी हुई है। वह गांव के चारागाह की जमीन है और गांव के निस्तारी की जगह है। यदि उस जमीन पर अवैध तरीके से फैक्ट्री अपनी सड़क बना लेगा तो मुझे लगता है कि जो approved plan था, उसमें यह व्यवस्था तो जरूर नहीं थी और इसी बात का गांव वालों ने एक बार नहीं, बल्कि कई बार विरोध किया है। मेरे पास उसके साक्ष्य हैं। इसीलिए वहां पर गांव वालों में रोष व्याप्त है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने डिटेल में जानकारी दी है कि स्कूल उसकी बाउंड्री वॉल से 200 मीटर दूर स्थित है और प्लांट की दूरी सिर्फ 500 मीटर है। वहां पर जो ट्रैफिक की हालत है, उस बात को लेकर और बच्चों की सुरक्षा को लेकर मैं और मेरे क्षेत्रवासी चिंतित हैं कि वहां पर बच्चे रोज स्कूल जा रहे हैं और यदि वहां पर हैवी ट्रैफिक होगा, बड़ी-बड़ी ट्रकें चलेंगी व हाइवा चलेगा तो दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ सकती है। माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह

यह था कि बच्चों व गांव की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उस प्लांट को कहीं और शिफ्ट किया जायें। ताकि बच्चों व गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्या माननीन मंत्री जी इसपर कोई निर्णय लेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी कह रहे हैं कि वहां पर गांव वालों में रोष व्याप्त है और वह धरना-प्रदर्शन करते हैं। ग्राम पंचायत ने स्वत: ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है और ग्राम सभा में भी इसका निराकरण हुआ है तो उनमें किसी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है। माननीय सदस्य जो सड़क की बात बता रहे हैं कि घास जमीन में सड़क बनी है तो उस सड़क के बारे में मुझसे जानकारी नहीं ली गई थी, गेट के बारे में जरूर जानकारी ली गई थी। उस जमीन का हम निरीक्षण करवा लेंगे कि घास जमीन में सड़क कैसे बनी है।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय मंत्री जी, क्या आप उसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- हम लोग उस सड़क को दिखवा लेंगे कि वहां पर क्या समस्या है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से एक और आग्रह है कि यदि यह कार्य नियम विरूद्ध हुआ है तो क्या आप ऐसे दोषी अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे ?

श्री लखन लाल देवांगन :- देखिये, सभी विभागों से उसको अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है। इसमें अधिकारियों के द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती गई हैं। यदि आपको कुछ लगता है तो आप हमें उसकी जानकारी दे दीजिएगा, हम उसको दिखवा लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। यह पर्याप्त हो गया। ध्यानाकर्षण की सूचना। श्री कुंवर सिंह निषाद।

ध्यानाकर्षण संख्या-02 (अनुपस्थित)

समय :
12.12 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

01. श्री अजय चंद्राकर
02. श्रीमती अनिला भेंडिया
03. श्री ब्यास कश्यप
04. श्री पुन्नूलाल मोहले
05 श्री रोहित साहू

समय :
12.13 बजे **याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में शामिल निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्री कुंवर सिंह निषाद
02. श्री धरम लाल कौशिक
03. श्री रिकेश सेन
04. श्री अनुज शर्मा

अध्यक्ष महोदय :- माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर माननीय किरण देव जी अपना भाषण प्रारंभ करेंगे।

समय :
12.14 बजे **माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)**

"माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं ।"

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। उनका अभिभाषण प्रदेश की प्रगति और विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ संकल्पना को दर्शाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की परिकल्पना वर्ष 2047 तक विकासशील भारत को विकसित भारत में परिवर्तित करने की है। इसी को लक्ष्य रखकर और गांव, गरीब, किसान व सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी की सरकार इसी दृढ़ संकल्पना के साथ अनेक कल्याणकारी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है और सिर्फ संचालित ही नहीं कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। सरकार बनने के पश्चात हमारी सरकार द्वारा सिर्फ सवा वर्ष में ही छत्तीसगढ़ में अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से पूरा छत्तीसगढ़ अंधकार के लपेटे में आ गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 वर्ष आपके नेतृत्व में जिस तरीके से अनेक कल्याणकारी योजनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही बल्कि पूरे देश के लिए एक मापदण्ड स्थापित किया था, उस समय की कई योजनाएं थी, जिन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर अनेक प्रदेशों में

उसका प्रभाव पड़ा और उन राज्यों ने उन योजनाओं को अपने राज्य में में संचालित कराने का काम किया था। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में ऐसी योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से जनता ने विगत विधान सभा चुनाव में और चुनाव के पूर्व हमारी बातों पर विश्वास व्यक्त किया है। गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बहनों के लिए, वंचितों के लिए योजनाएं बनाने का जिस तरह से वचन दिया था, सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने सवा साल में ही बहुत तेजी से उनको योजनाओं में परिवर्तित करके पूरे छत्तीसगढ़ में चहुमुंखी विकास प्रारंभ किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्लोगन है कि "हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे"। छत्तीसगढ़ का निर्माण बिना किसी खून-खराबे के, बिना किसी आंदोलन के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने सिर्फ अपने एक सभा में छत्तीसगढ़ की जनता को वचन दिया था और उसके कारण यहां लोकसभा के चुनाव में जनता ने अपना अटूट स्नेह, विश्वास और प्यार उनके इस व्यक्तित्व को दिया, उसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। पूरे देश में कई राज्यों का निर्माण हुआ तो उसमें लंबे समय तक आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक मात्र ऐसा राज्य रहा है, जिसमें हमारी सिर्फ एक मांग पर छत्तीसगढ़ के निर्माता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़वासियों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य दिया। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, "हमने ही बनाया है हम ही संवारेंगे" जब हम इस बात को कहते हैं, तो उन 15 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद यह सवा साल की सरकार, बीच का जो 5 साल कांग्रेस का कुशासन था, उन्होंने ऐसे कई अनेक वायदे जनता के समक्ष किये, अपने घोषणा-पत्र में 36 वादे किए, लेकिन उन्होंने एक भी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया। लेकिन जनता ने भी इसका प्रतिफल उन्हें दिया है। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बड़े कृत संकल्पित होकर माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने ऐसे सभी घोषणाओं को विधानसभा चुनाव के पहले जनता के समक्ष किया था, उन घोषणाओं को पूरा करने में लगे हैं। आधे से भी ज्यादा लगभग 65 से 70 प्रतिशत ऐसी योजनाएं हैं, जो गांवों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय था, उसका लाभ सभी को मिल रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारन्टी की योजना है, सवा साल में ही इसका अंतर देखने को मिला। पिछले 5 साल के कांग्रेस के कुशासन में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की, केन्द्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सभी के लिए जो आपके समय में ही तेजी के साथ उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका था, ऐसी कई योजनाएं हैं, जो पूरे देश में समग्र रूप से संचालित हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको इसलिए यहां पर संचालित नहीं होने दिया क्योंकि वह प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार की योजनाएं थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम कोरोना के समय को याद करें, तो कोरोना के समय का ख्याल करें। कोरोना के समय वैसे पूरे विश्व में हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का यह अद्भूत निर्णय रहा है, जिसमें पहली बार हमारे देश में हमारे देश की वैज्ञानिकों की मदद से ऐसे 2 वैक्सीन का निर्माण किया। यह 2 वैक्सीन सिर्फ हमारे दशवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देश के बाहर भी 112 देशों में यह वैक्सीन सप्लाई किया गया, जिसके कारण आज हम सब इस वातावरण में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमने करोड़ों लोगों की जीवन बचाने का काम किया है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार का प्रथम काम करते हुए जनता के हितों की सुरक्षा करना, जनता के हितों में काम करना और सर्वांगीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता से इन सवा महीने में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के माध्यम से पूरा हो रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ अपनी कही हुई बातों को पूरा किया है। क्योंकि ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से आपके सामने सदन में क्रमश: उसका उल्लेख कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण योजना में मैं महतारी वंदन योजना का उल्लेख करना चाहूंगा। ऐसे हमारी बहनें एवं माताएं जो वंचित परिवारों से हैं, क्योंकि समुचित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पर्वों एवं त्यौहारों का प्रदेश है। यहां छोटे-छोटे त्यौहार अलग-अलग समाजों में हैं और उनके लिए इस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनको सशक्त बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने की है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की माताओं एवं बहनों के लिए और हमारे प्रदेश के लगभग 70 लाख ऐसी बहनें हैं, जिनको प्रतिमाह के पहले तारीख में 1 हजार उनके खाते में डालने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने अपने वचन को निभाने का काम किया है। इससे जनता में विश्वास बढ़ा है, माताओं एवं बहनों में विश्वास बढ़ा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। मैं इसका जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि विगत पांच वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार रही है तब उन्होंने इस योजना को यहां पर संचालित होने नहीं दिया। क्योंकि उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में इतनी अनियमितताएं व्याप्त हो गई थीं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उनके कार्यकाल में उनकी सरकार के कद्दावर नेता व पंचायत मंत्री जी ने उस पर असंतोष व्यक्त करते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उस कार्यकाल में व्यापक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकार बनते ही पहली केबिनेट बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब यह निर्णय लिया और यह शपथ लिया कि हमारी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री जी की यह महत्वपूर्ण गारंटी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे कांग्रेस की सरकार दुर्भावनावश बंद करके रखी थी, इसमें अपना राज्यांश भी देना बंद कर दिया था, उसको जब तक मैं इसे पुन: संचालित नहीं करूंगा, जब तक उसकी स्वीकृति के फाईल पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री निवास में कदम नहीं रखूंगा

उसको उन्होंने संपूर्ण करके दिखाया है। (मेजों की थपथपाहट) इससे जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने ऐसे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। साथ ही नये वित्तीय वर्ष में और 3 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी का अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन मिशन। हमने देखा कि पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस की सरकार के समय इस योजना में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। समय-सीमा का बंधन टूट गया। इसमें अपने चहेते ठेकेदारों को काम देने का काम किया गया। यह जल जीवन मिशन पूरी जनता से जुड़ी हुई योजना है। इन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में और अभी भी ऐसे अधूरे काम करके छोड़ कर गये हैं, उसके लिए हमारी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से 40 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके लिए भी सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है, जो डबल इंजिन सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के 1 लाख 90 हजार 210 महिलाओं के खाते में 70 करोड़ से अधिक राशि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना द्वारा अंतरित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं, उनका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ ।(मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, इस देश और दुनिया की आधी आबादी हमारी बहनों से है, उनको समुचित रूप से और खासकर उन हमारी बहनों को, उन माताओं को, जो वंचित परिवार से आते हैं, उनको अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समुचित व्यवस्था की जाये, ऐसा निर्णय हमारी सरकार कर रही है । अध्यक्ष महोदय, कृषक उन्नति योजना एक ऐसी योजना है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाईयों का संकल्प था कि हमारी सरकार बनते ही 3100 रूपये प्रति क्विंटल में धान खरीदी करेंगे । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे अन्नदाताओं को प्रति एकड़ 21 क्विंटल 3100 रूपये में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों की बिना किसी मांग के पूर्व की दो व्रर्ष की बकाया राशि भी देने का निर्णय लिया है, अपने संकल्प को दूसरे वर्ष लगातार निभा रहे हैं, मैं इसके लिये भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि जो महत्वपूर्ण योजना है, जब मैं इस बात को कहता हूँ कि सभी समाज, सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों के लिये, समुचित योजनाओं के माध्यम से, सभी की चिन्ता करने का काम, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कर रहे हैं और सरकार में आने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की डबल इंजिन की सरकार जो उसे कर रही है, उसके लिये धन्यवाद के पात्र हैं । अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना माध्यम से प्रदेश के

24 लाख 31 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं, यह 6000 रूपये प्रतिवर्ष की योजना है और किसानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री का जो स्वच्छ भारत मिशन है, मैं जिन-जिन योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ, इसमें 80 प्रतिशत योजना वह है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हितग्राहियों को लाभ लेने से वंचित किया गया था । अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधानमंत्री आवास का विषय रखा था, इस योजना के तहत प्रदेश की सरकार ने 5 साल तक केन्द्र की योजनाओं से उन लोगों को वंचित रखा था, जो प्रधानमंत्री आवास के लिये पात्र थे । अध्यक्ष महोदय, मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में कहना चाहूँगा कि इसके द्वितीय चरण में 3 लाख 88 हजार ग्रामीण परिवार के घरों में शौचालयों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में 13,115 सामुदायिक शौचालय और उसके साथ-साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह विषय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में 146 ऐसे सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण किया गया है, जो इस बात का द्योतक है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ग्रामीण महिलाओं के सम्मान को बचाने की दृष्टि से, उनका सम्मान पूरी तरह से सुरक्षित करने की दृष्टि से शौचालय निर्माण का जो निर्णय लिया था, वह योजना पूरे देश में जिस तरीके से लागू हुआ, उसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को अनवरत रूप से चालू किया है, उसके लिए उन्हें बधाई। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में 341 पीएम श्री विद्यालय चालू किये गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यह भी अभूतपूर्व कदम है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5 लाख, 62 हजार ऐसे भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास किसानी के लिए खेती नहीं है, वे दूसरों के यहां मजदूरी का काम करती हैं और रोज रोजी कमाकर अपने घर जाती हैं, उनके लिए चिन्ता की गई है । पंडित दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से ऐसे 5 लाख, 62 हजार भूमिहीन किसानों को 10-10 हजार रूपए देने का निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं (मेजों की थपथपाहट)

समय :
12:32 बजे **(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब 15-20 वर्ष पूर्व आपने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया था । यह सारे निर्णयों के विषय में मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह दुनिया की आधी आबादी या हमारे देश की आबादी या छत्तीसगढ़ की आधी आबादी है, वह हमारी मातृ शक्ति की है, उनके लिए हमारे प्रदेश में स्व सहायता समूह का निर्माण किया गया था । पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने उनके लिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया, जो

उनको सम्बल प्रदान करे । वित्तीय वर्ष 2024-25 में एस.आर.एल.एम. के अंतर्गत 68 हजार से अधिक स्व सहायता समूहों को 1108 करोड़ रूपए का ऋण बैंकों के माध्यम से वितरित किया है, उसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं (मेजों की थपथपाहट) इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश की बहनों के लिए रेडी टू इट योजना के क्रियान्वयन का कार्य और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से यह काम कराया गया था । रेडी टू इट समूह का कार्य चरणबद्ध तरीके से पुन: स्व सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वचन को निभाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं और सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं । (मेजों की थपथपाहट) इसकी मांग हमारे प्रदेश की बहिनें बहुत समय से कर रही थीं ।

सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रदेश के 36,76,260 गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं। इसकी पीछे की भावना यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह बहुत भावनात्मक निर्णय है कि ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर अगर हम छत्तीसगढ़ की दृष्टि से बात करें तो हमारे प्रदेश की ग्रामीण महिलाएं वर्षों से चूल्हा-चौंका करती हैं तो जंगल में जाकर लकड़ी बीनकर, लकड़ी काटकर उसे चूल्हे में डालकर जिस तरीके से घर में भोजन पकाने का काम करती हैं तो धुआं जो है, वह चूल्हे से निकलकर उनकी ऑंखों के माध्यम से फेफड़े में जाकर उन महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करती हैं । इससे दो नुकसान होता है । पहला- उनके शरीर को हानि पहुंचती है, उसके अलावा जिस तरीके से जंगल से वृक्षों की कटाई या छोटे मोटे झाड़ियों से वन की संपदा है, उसका नुकसान होता है । यह दोनों हानियों को बचाने की दृष्टि से उज्जवला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ में भी 36,76,260 गैस कनेक्शन देने का निर्णय किया है, उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति◌ँ महोदया, पूर्ववर्ती 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में बस्तर, सरगुजा और कवर्धा के कुछ क्षेत्रों के लिए हमारे वनवासियों को मुख्य आजीविका तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए उनको 15 वर्ष तक अनुमति थी कि वे 15 दिनों तक तेंदूपत्ता संग्रहण का काम कर सकें। उन्हें चरण पादुका देने और उन्हें व्यवस्थित करने का काम किया गया।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- सभापति◌ँ महोदया, माननीय सदस्य बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वे तेंदूपत्ता तक आ गए। आप ये कृपा कर दीजिए कि महुआ के बारे में थोड़ा बखान करिए। उसकी विशेषता बताइए।

श्री राजेश मूणत :- उनका काम महुए से नहीं पड़ता, उनका काम सेल्फी से पड़ता है।

श्री किरण देव :- माननीया सभापति जी, विपक्ष अगर सामने न हो, तो बोलने में और भी कठिनाई होती है। तेंदूपत्ता के विषय में मैंने बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस सीजन में यह व्यवस्था थी कि वे 15 दिनों तक तेंदूपत्ता संग्रहण का काम करें, क्योंकि दूरस्थ ग्रामीण वनवासी क्षेत्रों में हमारे वनवासी परिवार इसे करते आ रहे थे। उनको चरण पादुका देने का काम भी आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्री डॉ. रमन सिंह जी के समय हुआ था, किन्तु पिछले पांच सालों में कॉग्रेस की सरकार ने यह बंद कर दिया। मैं तो बस्तर से आता हूं, एक से दो दिन के अंदर तेंदूपत्ता तोड़ाई के काम को बंद करवा दिया जाता था। ये निर्णय कांग्रेस की सरकार का वास्तव में अकर्मण्य निर्णय था। मैंने पहले भी इस बात का उल्लेख किया था कि कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष की सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार से लिप्त छत्तीसगढ़ बनाया। यही नहीं पूर्ववर्ती सरकार ने जो-जो काम चालू किए थे, जो योजनाएं चालू की थीं, उनको भी समाप्त करने का काम किया। इसे ध्यान में रखते हुए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक दर प्रति मानक बोरा 4000 रुपए से बढ़ाकर 5500 करने का जो निर्णय लिया है, ये स्वागतयोग्य है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) सभी सेक्टर/क्षेत्रों में काम करने का सरकार का जो निर्णय है कि सभी के लिए योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाएं, ताकि उनको लाभ मिले।

सभापति महोदया, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में श्रमिक हैं। इन पांच सालों में जिस तरीके से श्रमिकों का पलायन हुआ, क्योंकि उनके लिए कांग्रेस की सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, जिसके कारण हमारे श्रमिकों का तेज गति से पड़ोसी राज्यों में काम ढूढ़ने के लिए जाना होता था। इन श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए एक निर्णय लिया गया है। यह सुनने में तो बड़ा अलग लगता है, लेकिन इससे इनके लिए 24 घंटे के पारिश्रमिक की स्थिति बढ़ती है, इसलिए श्रमिकों के हितों को संरक्षित करते हुए अपनी व्यवस्था के अनुरुप दुकानों को 24 घंटे और सातों दिन खुले रखने का निर्णय किया गया है।

माननीय सभापति महोदया, हम शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, तो प्रदेश सरकार शिक्षा नीति के तहत बच्चों को कई बोलियों में शिक्षा दे रही है। अगर हम बस्तर के वनवासी क्षेत्र, सरगुजा के वनवासी क्षेत्र या फिर संपूर्ण छत्तीसगढ़ की बात करें, तो यहॉ भाषा और बोलियों की बहुलता है। हमारे बस्तर में तो प्रत्येक 20 किलोमीटर में बोली बदल जाती है। दूरस्थ अंचल के बच्चे अब तेजी के साथ शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं क्योंकि उनके परिवार में जिस तरह से जागरुकता बढ़ी है, उसके कारण वनवासी क्षेत्रों में भी वनवासी परिवार के बच्चे शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। सरकार ने ऐसे उपाय किए हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक की हिन्दी माध्यम

की पाठ्य पुस्तकों को क्यू-आर कोड युक्त किताबों में परिवर्तित किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी वे इससे जुड़ सके और हमारी जो अलग-अलग बोलियां हैं, उन पर उनको आसानी से शिक्षा प्राप्त हो सके।

मानमीय सभापति महोदया, मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उपमुख्यमंत्री (गृह) जी, स्वास्थ्य मंत्री जी सहित सभी मंत्रिमण्डल के सदस्यों को एक अत्यंत प्रमुख विषय के लिये धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं विशेषकर बस्तर क्षेत्र की "नियद नेल्लानार" योजना के लिये उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इसका हिन्दी में शाब्दिक अर्थ है "आपका अच्छा गांव"। इसमें सबकुछ समाहित है। मैं इसके लिये सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत-बहुत अभिनंदन करूंगा। (मेजों की थपथपाहट) इस योजना के तहत बस्तर क्षेत्र के आदिवासियों को कई मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें अलग-अलग विभागों को जोड़ा गया है और इसे कई मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। यह योजना पुलिस कैम्प के आस-पास के गांवों में लागू की जा रही है। क्योंकि हमारा जो संवेदनशील क्षेत्र बहुधा है और जो हमारे दूरस्थ अंचलों के क्षेत्र हैं, विशेषकर जो बस्तर क्षेत्र में शेष रह गये हैं, ऐसी जगहों पर उन गांवों में यह योजना लागू होगी। मैं आपके माध्यम से इस विषय में सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। 96 गांवों में 17 विभागों, 53 योजनाओं और 31 सुविधाओं के माध्यम से इस नियद नेल्लानार योजना के विकास का निर्णय लिया गया है और इस योजना का काम किया गया है। जिसके तहत 40 नये सुरक्षा कैम्प स्थापित किये गये हैं और 24 नये प्रस्तावित किये गये हैं। हमारे ऐसे दूरस्थ संवेदनशील क्षेत्रों में 28,114 ग्रामीण नियद नेल्लानार के लिये चिन्हांकित हुए हैं। उनके आधार कार्ड बनाने का जो निर्णय लिया गया है, वह वास्तव में बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। (मेजों की थपथपाहट) आज के वर्तमान समय में, आज के आधुनिक युग में हमारी जो पहचान है, वह आधार कार्ड है, जिससे हमारे बस्तर के लोग वंचित न हो जाये। हमारे शासन की समस्त योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हो, वह सभी आधार कार्ड से लिंक होती है। उन योजनाओं का लाभ उनको मिल सके, इस दृष्टि से यह निर्णय हुआ है, उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई। ऐसे अभूतपूर्व निर्णयों में से एक निर्णय और है। समय-समय पर हमारे बस्तर, सरगुजा जैसे दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में इसकी मांग होती थी, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा। अब बिना मोबाईल के तो कहीं काम ही नहीं होता है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय का मामला हो, चाहे जानकारी एकत्र करने का मामला हो। मोबाईल के माध्यम से सब कुछ, पूरी दुनिया अब लोगों के हाथों में है। नियद नेल्लानार योजना में अच्छा गांव के अंतर्गत जो योजना बनाई गई है, जिसमें करीब 521 मोबाईल टॉवर चालू किये गये हैं, उसके लिये भी बहुत-बहुत अभिनंदन। (मेजों की थपथपाहट) इसका काम हमारे कोलेक से लेकर बासागड़ा, ओरछा तक के क्षेत्रों में हुआ है, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। उसी क्रम में नियद नेल्लानार की कुछ विशेषताओं के बारे में और उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदया, उस क्षेत्र के उस

गांव में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत आदिवासियों को 14,818 आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन। यह वास्तव में अभूतपूर्व निर्णय है। जिनका राशनकार्ड अभी तक नहीं बना था, इस योजना के तहत 9,509 परिवारों का राशनकार्ड बनाया गया है। उसका केवल निर्णय ही नहीं हुआ है, वह लागू भी किया गया है, उनको राशनकार्ड प्राप्त हो गये हैं। इसी प्रकार हम वनाधिकार पट्टे की बात करते हैं। इस योजना के तहत 649 वनाधिकार पट्टे वितरित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में हमारे जवान, जो दिन-रात हम सब की सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर अपनी सेवाएं देते हैं। यदि वहां पर किसी प्रकार की केजुअल्टी या किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उनको समीपस्थ अस्पताल या राजधानी में इलाज के लिये लाने में जो असुविधा होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू की गयी है। यहां हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी भी विराजमान हैं। यह बस्तर के दूरस्थ अंचलों में पहली बार हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 68 हैलीपैड पूर्ण हो चुके हैं और 13 हैलीपैडों का निर्माण चल रहा है। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। (मेजों की थपथपाहट) नियद नेल्लानार के लिए इन तमाम सुविधाओं के अतिरिक्त 20 करोड़ रूपये का प्रावधान बजट में शामिल करने के लिए सरकार को बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। यह एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से हमको यह मालूम है कि पिछले 5 वर्षों में पी.एस. घोटाला हुआ। इसकी एक-एक परते खोली जाएं। आज सदन में विपक्ष सामने नहीं है। जिस तरीके से इन 5 वर्षों में इन्होंने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है। इस प्रदेश में जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, इसका जीता-जागता उदाहरण है कि पिछली सरकार ने जो लोक सेवा आयोग में भर्ती के माध्यम घोटाला किया। इन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनके साथ छल किया है। प्रदेश के लोक सेवा आयोग की भर्ती में जिस तरीके से भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार का खेल खेला गया, यह बात किसी से भी छुपी नहीं है। जब मैं आपके माध्यम से इस सदन में यह बात रख रहा हूँ तो अब यह बात भी बताना चाहूंगा कि अब हमारी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता लाते हुए, यू.पी.एस. सी. की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू की है तथा लोक सेवा आयोग 2021 की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, इसलिए यह मामला सी.बी.आई. को सौंपा। हमारी सरकार ने एक पारदर्शी निर्णय लेने का काम किया है। उसके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद।(मेजों की थपथपाहट) आपने यह सिद्ध किया है कि हमारी सरकार जो कहती है, वह करती है। यह हमारी सरकार की योजनाओं और कार्यप्रणाली में परिलक्षित होता है। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने भी अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया है। हमारी सरकार ने इतने क्षेत्र के समग्र विकास और युवा विकास की दृष्टि से योजनाएं बनायी हैं। हम सभी यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी किशोरावस्था बतायी है। स्वामी जी के विचार हम सबके

लिए प्रेरक हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पूरा देश उनके जन्मदिवस को युवा दिवस के रूप में मनाता है। मैं भी अपने आदर्श के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को मानता हूँ। जिस तरीके से हमारी सरकार ने उन्हें आदर्श मानते हुए, युवाओं की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है, जिससे युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा मिले। इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

सभापति महोदया :- माननीय किरण देव जी, अभी दो सदस्यों को और बोलना है। इसलिए थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदया, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदया, यहां सदन में माननीय सदस्य पहली बार बोल रहे हैं।

श्री किरण देव :- माननीय सभापति महोदया, ऐसी कई योजनाओं के नाम बताकर अपनी बात करूंगा, जो प्रदेश में संचालित हो रही हैं, यह हमारे युवाओं के लिए रोल मॉडल बनी हुई हैं। नवा रायपुर अटल नगर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने की दिशा में काम कर हो है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण योजना है। बीपीओ और केपीओ कंपनियों को आकर्षित करने आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। यह महत्वपूर्ण है। दिव्यांग व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने 11 घरौंदा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। यह एक नई योजना है। हमारी प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की चिन्ता करते हुए, उन्हें आश्रय प्रदान करने के लिए 11 घरौंदा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं नशामुक्ति अभियान का जरूर उल्लेख करूंगा। यह गंभीर समाजिक समस्या है। हमारा बस्तर क्षेत्र से लगा हुआ जो बॉर्डर का राज्य है, हम हमेशा इस बात को उठाते रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरे प्रदेश को नशे के अंधकार में ढकेलने का काम किया है। आज तक छत्तीसगढ़ प्रदेश उसका परिणाम भुगत रहा है। इस दृष्टि से यह गंभीर समाजिक समस्या है। हमारे प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी न हो, हमारी सरकार इसकी रोकथाम के लिए दृढ़संकल्पित है। मैं केवल इतना उल्लेख करूंगा। वर्ष 2024 में नशे के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए डी.पी.सी. एक्ट के अंतर्गत लेकर 1 हजार 337 प्रकरणों में से 2139 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने का जो निर्णय है, यह वास्तव में बहुत ही बधाई और अभिनंदन के योग्य निर्णय है। (मेजों की थपथपाहट) कई ऐसे नशे के कारोबार में संलिप्त और 24 हजार 361 किलोग्राम ग्राम गांजा, 909 नग पौधा, ब्राऊन शुगर, नशीली दवा, टेबलेट इस तरीके की कई दवाओं को जब्त करने का काम किया है, जो 05 साल कांग्रेस की सरकार में निरंतर अनवरत रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में व्याप्त था। पहली बार

P.I.T.N.D.P.S. act के अंतर्गत तैयार 181 प्रकरणों में 47 आदतन आपराधियों को निरूद्ध किया गया है। प्रदेश में पहली बार नशे के व्यापार में जो लोग जुड़े रहे हैं, उनको सिर्फ निरूद्ध ही नहीं किया गया है बल्कि अर्जित संपत्तियों को चिन्हांकित कर 4 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। राज्य में नशे के व्यापार के विरूद्ध कार्रवाई हेतु एंटी नॉरकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। यह क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर रखना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की बदौलत हमारे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग रेलवे स्टेशनों के पुर्नविकास के साथ-साथ 32 ऐसे अमृत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। रेलवे नेटवर्क विस्तार के लिए 26 परियोजनाओं के माध्यम से 2768 किलोमीटर नई रेल पटरियां 38,378 करोड़ रुपये की लागत से बिछाई गई हैं। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि सभी को बोलना है, हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय अजय चन्द्राकर जी, राजेश मूणत जी ने इस विषय को रखा है। यह सारी योजनाएं हमारी सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सवा साल में संचालित किया जिसका लाभ सीधे-सीधे प्रदेश की जनता को मिला। जब हम डबल इंजन सरकार की बात करते थे, उसका लाभ सीधे-सीधे छत्तीसढ़वासियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तेज गति से मिलने लगा है। छत्तीसगढ़ में हम तो डबल इंजन सरकार की बात करते थे। जनता ने अपना इतना विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है कि आप हमारे दल के अध्यक्ष हैं, आप जो बोलेंगे हम लोगों के लिए वह नीति वाक्य है। हम लोग उस लाईन को आपके पीछे-पीछे लंबा करेंगे। लेकिन आप एक घोषणा मत करियेगा, पुन्नूलाल जी ने अपना इंतजाम कर लिया है। अब वह सिंगल नहीं हैं, डबल हैं।

श्री किरण देव :- मैं डबल इंजन नहीं, चार इंजन की बात कर रहा था। मैं आपके माध्यम से जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार की योजनाओं पर, मोदी जी की योजनाओं पर इतना विश्वास व्यक्त किया है कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों के चारों इंजन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव में जिस तरीके से सरकार की योजनाओं पर अपनी प्रतिबद्धता और अपना विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से जनता का अभिवादन करता हूं। (मेंजों की थपथपाहट) मै पुन: माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सभापति महोदय, आपने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में अपना विषय रखने के लिए समय दिया, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले जी। 5 मिनट में अपनी बात खत्म करिये।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, उनकी उम्र का ध्यान रखिये। वह 5 मिनट में तो चालू करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आज यदि माननीय वरिष्ठतम विधायक पुन्नूलाल मोहले जी बोलते हैं तो उनकी बात को गंभीरता से मत लीजियेगा। वह आज बहुत खुश हैं। वह लाईन से हटकर भी बोल सकते हैं।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- मैं आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी को बधाई देता हूं। आज माननीय अजय चन्द्राकर जी ने शुभ संदेश दिया। मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप पार्टी कब दे रहे हैं?

श्री राजेश मूणत :- आपका माईक बार-बार चालू और बंद क्यों हो रहा है?

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री धरमलाल कौशिक जी ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं धरमलाल कौशिक जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया है, फिर 5 मिनट में ही बोलूंगा। सभापति महोदय, यह विधान सभा हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है और हम लोग इस मंदिर के पूजारी हैं । पूजारी लोग यहां अपनी जनता की सुख-शांति और अच्छे विचारों के लिये, समाज की सेवा के लिये तथा वहां के लोगों के आम कामों के लिये आशीर्वाद मांगते हैं इस वजह से हम सभी पूजारी हैं । आज इस पूजा में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के लिये अनेक कार्य किये हैं, मैं उन कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी ने राज्य बनाया, यदि छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनता तो आज हम लोग यहां नहीं बैठ पाते । मैं माननीय अटल जी का अभिनंदन करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं । प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश एवं समाज की सेवा के लिये भी अपना मार्गदर्शन दिया है और आज उसी मार्गदर्शन में हम सभी लोग चल रहे हैं । मैं उन्हें भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

समय :
12.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले किसानों की बात करूं तो किसानों के भविष्य को देखते हुए हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन जी ने किसानों की धान खरीदी का एक बड़ा कार्य किया है । आज किसानों की धान खरीदी में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान लेने की व्यवस्था की तथा 3100 रूपये प्रति क्विंटल देने की व्यवस्था की और 149 मीट्रिक टन धान की खरीदी हमारी सरकार ने की, इसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं । किसान अब नहीं है परेशान, उनका बढ़ रहा है स्वाभिमान और सरकार समय पर कर रही है भुगतान, यह है किसानों के लिये माननीय विष्णुदेव साय ने किया है काम । मैं इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता

हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम आवास योजना के बारे में बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख आवास कर दिये पास, लोगों को नहीं किया उदास और 18 लाख आवास हो गये पास । 18 लाख आवास पाने से आम नागरिकों में खुशी की लहर है, मैं अगर दूसरी बात कहूं तो 3 लाख और अतिरिक्त आवास पास हो गए । हमारे माननीय कृषि मंत्री जी आये थे और उन्होंने भी इसे पास किया है, हमें और भी अतिरिक्त मिला है । अब आवास तो पास हो गये और चावल की व्यवस्था चूंकि हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा 68 लाख लोगों को पिछले समय 1 रूपए में खाद्य दिया जाता था अब 1 रूपए की जगह मुफ्त में खाद्य दिया जा रहा है अर्थात् राशन की व्यवस्था हो गयी । राशन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था और किसानों को किसानी में उनके धान की व्यवस्था ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम पेयजल की बात करें तो 40 लाख लोगों को नल-जल योजना के माध्यम से हमारे माननीय पी.एच.ई. मंत्री अरूण साव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा लोगों के घर-घर तक पानी पहुंचाने का भी काम किया गया है जिससे हमारी मां-बहनें, बहू-बेटियां जो दूर में पानी भरने के लिये जाती थीं, वे अपने घर में ही बटन दबाकर नल का पानी पी रही हैं जिससे काफी बचत हो रही है । उज्ज्वला गैस से बहुत लोगों को फायदा हुआ है । हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्जवला गैस मिलने से अब लोग चूल्हे की स्थिति में नहीं जायेंगे और न ही अब वे लकड़ियां खोज रहे हैं । अब वे खुद गैस जला रहे हैं, गैस, अब नहीं देना पड़ता है ज्यादा केश और मिल रहा है उसे फोकट में गैस । इससे हमारी माता-बहनों के लिये आज बहुत अच्छा हो गया है । मैं दूसरी बात करूं तो 1000 रूपये में महतारी वंदन योजना । भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने लगाया चंदन और लागू हो गयी महतारी योजना वंदन । हमारी माताएं-बहनें 1000-1000 रूपए पा रही हैं, हमारी बहू-बेटियां पा रही हैं । वे अब 1000 रूपए पा रही हैं और सामान खरीदने फोकट में जा रहे हैं बाजार और पा रहे हैं प्रति महीने एक-एक हजार । एक-एक हजार से बढ़ रहा है उनका स्वाभिमान, बढ़ा मान-सम्मान । अब वह अपने पति की तरफ ध्यान नहीं देती हैं । उनके पति कहते हैं कि भई मुझे काम है तो 200-400 रूपए दे दो, अब पति अपनी पत्नि से पैसा मांग रहा है । ऐसी स्थिति कौन लाया तो यह स्थिति माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार लेकर आयी है, यदि महिलाओं को 1000 रूपए नहीं देते तो महिलाओं का सम्मान नहीं बढ़ता । आज महिला अपने पैरों में खड़ी हुई है और स्वावलम्बी बनी है, उन्हें स्वावलम्बी योजना के अंतर्गत और 11 करोड़ रूपए की राशि ऋण के रूप में दी जा रही है । इससे यदि वह महिलायें कोई भी जैसे उद्योग-धंधे के लिये कार्य करती हैं तो इसके लिये हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार ने यह काम किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम बारिकी से बात करें और दूसरी बात करें तो हमारी सरकार ने किसान भाईयों को किसान कल्याण योजना में 14 महीने में 1 लाख करोड़ रूपए का लाभ दिया है ।

अगर हम दूसरी बात करें तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 14 लाख कृषकों को 10-10 हजार रूपए की राशि अलग से दी गयी है, जिसमें 25 लाख 9 हजार 514 कृषक लाभांवित हो चुके हैं ।

समय :

1.00 बजे

माननीय अध्यक्ष महोदय, खेती-किसानी को हाइटेक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। फसल का उचित दाम मिलने से किसान भाइयों को पर्याप्त बचत हो रही है। प्रोत्साहन से अधिक कृषि ट्रैक्टर की बिक्री हुई, जिससे किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं और ट्रैक्टर का अच्छे से उपयोग भी कर रहे हैं, जिससे वे अपने स्वतः पैर में खड़े हुए हैं। जैविक खेती के लिए सरकार ने 22 हजार 180 हेक्टेयर रकबे का जैविक जी.पी.एस. प्रमाणीकरण कर 39 हजार 950 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। युवाओं के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ए.आई. के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के युवाओं को जोड़ने हेतु अटल नगर नवा रायपुर में 14 एकड़ डेटा सेंटर भी बना रहे हैं। रेलवे नेटवर्क की हम बात करें माननीय हमारे विष्णु साय जी की सरकार ने अगर मैं बात करूं तो बिलासपुर से डोंगरगढ़ रेलवे लाइन के लिए भी 300 करोड़ की राशि दी है, जिससे वे लोग जिन्होंने रेल नहीं देखा है, वे अब रेलवे लाइन बनने से रेल में जायेंगे, उनकी आधुनिक स्थिति भी सुधरेगी और वे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ेंगे तथा उन्हें नया प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वर्ष 2024-25 में 899 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है। अगर आप केंद्रीय सड़क निधि की बात करें तो 1204 करोड़ रूपए के 17 रोड स्वीकृत हुए। ए.डी.बी. (एशियन डेवलपमेंट बैंक) माध्यम से 3370 करोड़ रूपए की 826 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से राज्य में महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों के लिए 5784 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। इनमें 451 कार्य पूर्ण कर लिये गए हैं तथा 57 कार्य प्रगति पर हैं। नई औद्योगिक नीति की बात करें तो नई औद्योगिक नीति से व्यापारियों का मनोबल बढ़ा है।

श्री राजेश मूणत :- मोहले जी, आप इतनी गंभीरता से बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, स्वयं आ गये हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अब सप्ताह में 24 घंटे व्यापारियों की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे लोग आत्मनिर्भर रहेंगे और अच्छे कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 31 हजार 956 आवेदनों पर 55 करोड़ 61 लाख रूपए का ऋण व्यवसायों को बढ़ाने के लिए स्वीकृत किया गया है। पी.एम. विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों के 49 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए संचालित 9438 बालवाड़ियों में गतिविधि पुस्तिका, अभ्यास पुस्तिका के साथ दैनिक शिक्षण योजना तैयार की गई है। खेल-खेल में बच्चों को सिखाने में 30 हजार 522 विद्यालयों में टॉय किट का वितरण किया गया है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं

धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया गया। दिल्ली की सरकार भी 5-5 किलो प्रति व्यक्ति को दे रही है चाहे बच्चे हों, चाहे सियान हों और हमारे यहां की सरकार भी 68 लाख परिवारों को दे रही है। दो प्रकार के फायदा भा.ज.पा. का कायदा और चावल में दो प्रकार का है, आम नागरिक को मुफ्त में फायदा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के अंतर्गत 3 लाख 88 हजार परिवारों के घरों में शौचालय की व्यवस्था सरकार ने की है और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 146 शौचालय बने हैं। 13 हजार 115 सामुदायिक शौचालय भी बने हैं। इस तरह शौचालय के क्षेत्र में हम चाहे गांव में जाएं, चाहे शहर में जाएं, अपने घर में रहें, माननीय हमारे माननीय मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने शौचालय की व्यवस्था की। पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था और पढ़ाई में पी.एम. श्री विद्यालय की व्यवस्था, यहां तक कि बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, किसानों के लिए मुफ्त में 3 से 5 हार्स पावर के पम्प की व्यवस्था तो सभी प्रकार की व्यवस्था सरकार ने की है, जिससे लोग आत्मनिर्भर हुए हैं और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहले नंबर में आ रहा है।

श्री राजेश मूणत :- माननीय मोहले जी, माननीय गुरू जी पूछ रहे हैं कि हैंड पंप की व्यवस्था है या नहीं है?

श्री पुन्नूलाल मोहले :- क्या?

श्री राजेश मूणत :- हैंड पंप की व्यवस्था है या नहीं है? (हंसी)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप जारी रखिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- हमारी सरकार ने 14 महीने में 300 से अधिक नक्सली को मार गिराया है और 972 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है तथा 1183 गिरफ्तार किए गए हैं और आत्मसमर्पित नक्सलियों तथा नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पुनर्वास नीति के तहत 15 हजार प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये गये हैं। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं। माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। नक्सली अब आखिरी सांस ले रहे हैं। जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या दूर होगी। अयोध्या में हमारे प्रभु रामलला का मंदिर बना, उनके दर्शन के लिए शासन के माध्यम से 20 हजार लोग गए, उनके आने-जाने की सुविधा, रूकने, खाने, चिकित्सा सुविधा भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उपलब्ध कराई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद् देता हूं । प्रयागराज महाकुंभ के लिए, छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों के लिए वहां रहने की, खाने की, दवाईयों एवं अन्य व्यवस्थाएं की गई, जिससे महाकुंभ में लोगों ने स्नान कर अपना जीवन कृतार्थ किया है । राजिम कुंभ का भी आयोजन हमारी सरकार द्वारा किया गया है । इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई एवं धन्यवाद् देता हूं एवं

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, धन्यवाद् ।

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उनका अभिभाषण प्रदेश की प्रगति एवं विकास के प्रति हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं अपने विपक्ष के साथियों को भी सुन रहा था । बड़े आश्चर्य की बात है कि अभिभाषण के किसी भी बिंदु पर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है । मैं पिछले कुछ दिनों से टी.व्ही.चैनल्स होने वाली डिबेट में अपनी पार्टी के पक्ष में उपस्थित रहता हूं । कल एक टी.व्ही. चैनल पर मैं था तो उसमें हमारे विपक्ष के साथियों ने कहा कि ई.डी., सी.बी.आई. जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को भाजपा अपने इशारों पर नचाती है । मैंने कहा कि पिछले 15 साल तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी की सरकार थी । केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी । पिछले 15 सालों तक जब आप माननीय मुख्यमंत्री थे तो उस समय के कार्यकाल में लगातार केन्द्र में आपकी सरकार होने के बावजूद भी आप एक भ्रष्टाचार को साबित नहीं कर पाए । आज जिस प्रकार से आपके शासनकाल के समस्त भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, वे जेल में बंद हैं । लेकिन आपके मुख्य मंत्रित्वकाल के अंतर्गत एक भी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा । वैसे ही विष्णुदेव साय जी की सरकार लगातार एक वर्ष से जिस प्रकार से लोगों के हित में काम कर रही है । चाहे किसानों के हित की बात हो, चाहे युवाओं के हित की बात हो, चाहे मजदूरों के हित की बात हो, चाहे महिलाओं के विषय पर बात हो । हम लगातार काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों ने बड़ी-बड़ी बात कही है । कानून-व्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही थी । अभी तो वे नहीं है, मैं उनसे पूछता कि कानून-व्यवस्था को खराब करने के संबंध में जो भी अपराधी पकड़ा रहे हैं, उन अपराधियों में सिर्फ कांग्रेस से लिप्त पदाधिकारी ही क्यों ? किसी अपराध में कांग्रेस का विधायक संलिप्त होता है, कोई एन.एस.यू.आई. का जिला अध्यक्ष होता है, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष संलिप्त रहता है । यह विषय प्रदेश के लोगों को जानने की आवश्यकता है । कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ , विष्णुदेव साय जी की सरकार के खिलाफ कांग्रेस के हमारे मित्र एक षड्यंत्र रच रहे हैं । जिस प्रकार आज महिलाओं को महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह एक हजार रूपए मिल रहा है । हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि हम यह पैसा जबरदस्ती दे रहे हैं, वे पैसा लेना नहीं चाहते । वे तरह-तरह की अफ़वाहों को उड़ाने का काम करते हैं । वे इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारी तरफ से एक माह भी विलम्ब हो जाए और उन्हें राजनीति करने का मौका मिल जाए । अध्यक्ष महोदय, यह एकदम स्पष्ट है कि लगातार महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रति माह हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को लाभ मिल रहा है । यह सबसे बड़ा गर्व का विषय है कि उनको उनका अधिकार मिल रहा है । विष्णुदेव साय जी की सरकार है और यह सरकार महिलाओं के हित में काम करने जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी हमारे प्रदेश में हम लोगों ने एक बड़ी छलांग लगाई है । लगातार हमारे वित्त मंत्री का प्रयास है, हमारे तमाम मंत्रियों का प्रयास है, हमारे आदरणीय विजय शर्मा जी का प्रयास है कि हम आई.टी. सेक्टर को अपने क्षेत्र में स्थापित करें । आज हमारे प्रदेश के बच्चे पुणे, बैंगलोर, मुम्बई में आई.टी. सेक्टर में काम कर रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे आई.टी. सेक्टर में छत्तीसगढ़ में ही काम करे। हमारी विष्णुदेव साय की सरकार के माध्यम से बड़ी-बड़ी कंपनियों को लाने का काम, एम.ओ.यू. का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं जब कांग्रेस के इतने मैच्योर पालिटिशियन को देखता हूं, मैं उनकी बातों को सुनता हूं, वे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हम कब सदन से बाहर चले जाएं, हम कब सदन से बहिष्कृत हो जाए, हम कब यहां से पीछा छुड़ाएं। न सदन में चर्चा करने को तैयार रहते हैं, न कोई सड़क पर बात करने को तैयार रहते हैं, न विपक्ष की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, सिर्फ राज्यपाल जी के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करना है। एक ऐसे संवैधानिक पद पर जब राज्यपाल जी बोल रहे होते हैं, वैसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री जी का टोकना ठीक नहीं है। क्योंकि जब राज्यपाल जी अभिभाषण करते हैं तो सरकार के हितों की बात करते हैं। जब भूपेश बघेल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़ते थे, उस समय हमारे लोग संवैधानिक रूप से उसका पालन करते थे, सुनते थे। विपक्ष के साथी माननीय राज्यपाल जी की मर्यादा को बार-बार भंग करने का काम करते आए हैं। मैं उमेश पटेल जी को सुन रहा था, जो दो बार के विधायक हैं, मैं नेता विपक्ष को सुनते रहता हूं, मैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुनते रहता हूं, कोई भी ऐसा हित जो छत्तीसगढ़ के विषय पर हो, कोई भी विकास की गति में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल जी के अभिभाषण का लगातार आलोचना करने का काम कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ हुआ जिसमें 66 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया लेकिन चरणदास महंत जी, नेता विपक्ष और भूपेश बघेल जी कुंभ में नहीं गये, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना था, उनको हिन्दुत्व का विरोध करना था। यह कौशल्या माता की धरती है, कौशल्या माता की धरती को भी ये [xx] करने का काम करते हैं। आप शराब घोटाले की बात कर लीजिए। इन्होंने जिस प्रकार से शराब नीति बनाई, उस शराब नीति में भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और [xx] करने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है। महादेव सट्टा ऐप को जिस प्रकार से संचालित किया गया, इसमें हजारों युवाओं को लिप्त किया गया, आज विष्णुदेव साय जी की सरकार सही दिशा में चल रही है। लोगों को रोजगार कैसे मिले, उसकी चिंता विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। लोगों को काम कैसे मिले, उसकी चिंता कर रहे हैं। किसानों के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, उसकी चिंता विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को

लगातार देखता हूं, सुनता हूं, उनकी जो सदन के प्रति कार्यशैली रहती है, गंभीरता कहीं नहीं दिखती है। उसका जो कारण है, वह सिर्फ एक ही है कि वे कैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश को [xx] करने का काम करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 18 लाख आवासों के लिए पहली केबिनेट में कलम चलाया और पहली केबिनेट में ही यह तय किया कि गरीबों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि हर गरीब का पक्का मकान हो, उस मकान को पाने का अधिकार उस गरीब का होना चाहिए, यह विष्णुदेव साय जी की सरकार ने करके दिखाया और हमने उनको 18 लाख आवास दिया। हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। हमने किसानों को उनका बकाया बोनस दिया, हमने किसानों को खुशहाल करने के लिए नई-नई योजना लेकर आए, हम युवाओं के लिए नई योजना लेकर आ रहे हैं। अगर हम सामूहिक विवाह की बात करें, कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक कारणों से विवाह नहीं कर पाते थे लेकिन महिला बाल विकास मंत्री जी का एक अभिन्न प्रयास रहा, जो भी ऐसे लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत विवाह कराया जाएगा। ऐसी न जाने कितनी बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं। हमारी सरकार की इस एक साल के कार्यकाल में हम लगातार जनता के बीच पहुंचे हैं। जहां तक साफ पानी की बात है, आज लोग आलोचना करते हैं, टंकी बन गया है, पाईपलाईन बिछ गयी है लेकिन पानी नहीं आता है। हमारे विपक्ष के साथियों को बताना चाहिए कि कहां पर, किस गांव में पानी नहीं आता है, यहां पर सिर्फ हो हल्ला कर देना, डिबेट में हो हल्ला कर देने से नहीं चलेगा। इनके जो नेता हैं, एक बंद कमरे में पत्र लिख देते हैं, उसके तहत् टी.व्ही. चैनलों पर डिबेट हो जाता है, इनके पास कोई आधार नहीं है। मैं विपक्ष के साथियों को लगातार चैलेंज करता हूं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहां पर गलत है, आप लिखकर दीजिए। आप बताईए कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहां पर अनियमितता पाई गयी है, आप नहीं बता पाएंगे। आप इसलिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पढ़ा है, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के हित और विष्णु देव साय जी की सरकार द्वारा किये गये कार्यों को ही बताया है। आज उद्योग की दिशा में हमारे मंत्री लखन लाल देवांगन जी के द्वारा लगातार कैसे हम यहां पर investors को लेकर आये, कैसे नये उद्योग स्थापित करे, कैसे युवाओं को रोजगार दिला सके और कैसे लोगों को काम दे सके, इस दिशा में एक बड़ी पहल करने का प्रयास चल रहा है। भूमिहीन लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारे राजस्व विभाग के मंत्री माननीय टंक राम वर्मा जी के द्वारा लगातार प्रयास चल रहा है। यदि हम नगरीय प्रशासन विभाग की बात करे तो भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार लोगों को न रोड दे पाई, न नाली दे पाई, न लाइट दे पाई और न बिजली दे पाई। उन मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम अरूण साव जी और उनका नगरीय प्रशासन विभाग कर रहा है। यदि हम विजय शर्मा जी के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बात करे तो गांव-गांव में सड़क बनवाने व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय ओ.पी. चौधरी जी वित्त मंत्री हैं और उनकी सोच व आप सब

लोगों के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से आज कोई यह नहीं बोल सकता है कि हमारे पास वित्तीय संकट है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी के नेतृत्व में हमको यही सिखाया जाता है कि आपको छत्तीसगढ़ में अनुशासन के साथ काम करना है और सदन में आपका व्यवहार, चाल, चरित्र व चेहरा सकारात्मक होना चाहिए। आज हम लोग इसी दिशा में काम करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना जानता हूं कि यदि आपको संपूर्ण विधायक बनना है तो उसके तीन कारण होने चाहिए और वह मुझे विपक्ष के साथियों में नहीं दिखता है। पहला है कि आपको संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में सीखना चाहिए, जिसे यह कभी सीखने का प्रयास नहीं करते है। दूसरा है, जिस क्षेत्र की जनता आपको जिताती है, उस क्षेत्र की जनता के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। लेकिन मैं यह देखता हूं कि यह अपने क्षेत्र में भी नदारत रहते हैं और कहीं न कहीं अंत में लालच देकर वोट पाने की इनकी जो कला है, उसमें यह माहिर हो जाते हैं। हम और हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार लगातार अपनी दिशा में काम कर रही है। यहां पर हमारे जितने सीनियर विधायक बैठे हुए हैं, हम सभी मिलकर व माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार कैसे छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़े व कैसे कौशल्या माता की यह धरती पूरे देश भर में आगे बढ़े, इसके लिए लगातार चिंता कर रही है। मैं विपक्ष की बातों को देख व सुन रहा था, उनका काम सिर्फ आधारहीन आरोप लगाना था। आज इस सदन के माध्यम से मैं अकेला रिकेश सेन विपक्ष के सभी विधायकों को चैलेंज करता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में एक भी त्रुटि निकालकर बताइये कि आपने इस प्रदेश का विकास नहीं किया है। आप यह बता दीजिये। लेकिन आप यह नहीं बता पायेंगे, क्योंकि इनको तो बात-बात में सदन का बहिष्कार करना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह मेरा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे आदेशित किया। जिसकी वजह से मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। निश्चित रूप से माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए है और इसके लिए हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार संकल्पित है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अब अंत में नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरण दास महंत जी। (अनुपस्थित)

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.19 से 3.00 बजे तक अंतराल)

समय
3.00 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

श्री राजेश मूणत (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा है। प्रदेश की एक गंभीर पार्टी जो लोकतन्त्र का चुनाव तो हार चुकी है, मैदान भी हार चुकी है। जब प्रदेश के विषय को उठाने का अवसर है, नेता प्रतिपक्ष से लेकर सब लोग यहां से बहिर्गमन करके गये हैं, तो यह इस प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि आप उनसे request कर दें ताकि वह कम से कम आ जाये, तो कम से कम इस प्रदेश में यह तो लगेगा कि वाकई में वह इस प्रदेश की जनता के प्रति चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के प्रति उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण पर चर्चा का शुभारंभ माननीय धरम लाल कौशिक जी ने किया। इस पूरी चर्चा में श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री धर्मजीत सिंह जी, श्री उमेश पटेल, श्रीमती गोमती साय, श्री विक्रम मण्डावी, श्री गुरू खुशवंत साहेब, श्री रामकुमार यादव, श्री प्रबोध मिंज, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती चातुरी नंद, श्री किरण देव, श्री पुन्नू लाल मोहले एवं श्री रिकेश सेन जी ने भाग लिया। मैं सबसे पहले उनको अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने विस्तार से हमारी सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया है। हम इसके लिए उनका अत्यंत आभारी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता-जनार्दन ने अपनी मोहर विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों के निर्वाचन में लगाई है। जनता का भरपूर स्नेह और जनादेश मिला और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का स्कोर शून्य रहा। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस की स्थिति ऐसी क्यों बनी ? यह उनके पांच वर्ष के कुशासन और अराजकता पर जनता का जवाब था।

अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने महापौर का अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि योग्य प्रत्याशी की जगह अपने गुट के अपने कृपा पात्र को महापौर बनवा दिया जाये। थोपे हुए महापौर, पार्षद का चुनाव भी हमारे एक जमीनी कार्यकर्ता से हार गये। (मेजों की थपथपाहट) हमने इस अलोकतान्त्रिक परम्परा को समाप्त किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार का कुशासन एवं भ्रष्टाचार से बनाये हुए गड्ढों को पाटते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हमने कई नई राह खोली है। केवल कुशासन और भ्रष्टाचार ही कांग्रेस सरकार की सच्चाई नहीं थी, अपितु संवेदनहीनता इस सरकार का सबसे कुरूप चेहरा था। रोटी और कपड़ा के साथ मकान, मनुष्य की सबसे

बुनियादी जरूरत होती है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की थी। छत्तीसगढ़ के 18 लाख लोग मकान की आस में रहे, लेकिन संवेदनहीन कांग्रेस की सरकार ने आम जनता की तकलीफ की ओर नजर भी नहीं फेरी। भूपेश जी, आज यहां पर नहीं हैं, आज यहां पूरा विपक्ष नदारत है। लेकिन केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास के लिए अपना हिस्सा तो दे रही थी, लेकिन कांग्रेस ने राज्यांश क्यों नहीं दिया, गरीबों के आवास के लिए जरूरी संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई ? आज विपक्ष नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं। कांग्रेस मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ साथी आपको राशि देने के लिए पत्र लिखते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में गरीब लोग कभी थे ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। हमने शपथ ग्रहण के अगले दिन ही केबिनेट में 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिए। नये वित्तीय वर्ष के लिए भी 3 लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए हैं। इनके लिए मार्च तक सर्वे पूरा हो जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मकान की बात चल रही है तो एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि हम मकान की मजबूती के लिए सरिया भी उपयोग करते हैं। सरिया अच्छी Quality का नहीं हुआ तो मकान कब भरभरा कर गिर जाये, यह कहा नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, राज्य सिविल सेवा, शासन प्रणाली की मजबूती के लिए सरिये की तरह काम करती है। वर्ष 2021 में पी.एस.सी. की परीक्षा हुई, जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले रहे। डिप्टी कलेक्टरों के पदों में कांग्रेस नेताओं के परिजन दिखें, पी.एस.सी. के अधिकारियों के बच्चे नजर आयें। उस दिन छत्तीसगढ़ के हर युवा का सपना टूट गया था। युवा सरकार से शिकायत करते रहे। सरकार की तरफ से एक लाईन की बाईट आती थी कि शिकायत मिलगी तो कार्रवाई करेंगे। पूरे सिस्टम को पता था कि सिविल सेवा के ढांचे में भ्रष्टाचार के नकली सर्वे की आपूर्ति हो चुकी है और यह पूरे ढांचे को तबाह कर देगा, फिर भी सिस्टम की चुप्पी दिल तोड़ देने वाली थी। अध्यक्ष महोदय, महाभारत की कहानी हर युग में दोहराई जाती है। दुशासन, दुर्योधन और शकुनि छल के बल पर जुआ खेलते हैं और द्रौपदी का चीरहरण होता है। इस कहानी में सर्वाधिक पीड़ा का विषय धृतराष्ट्र की चुप्पी थी। वे राजा थे। उनकी जिम्मेदारी अधिक थी कि उनके दरबार में हो रहा यह अंधेर रूके, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें उनकी सहमति थी। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जब छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं को आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी सरकार ने इस मामले को सी.बी.आई. को सौंपा। सी.बी.आई. तेजी से मामले की जांच कर रही है और कुछ आरोपी सलाखों के पीछे हैं, कुछ कतार में भी हैं। इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ बीते कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। पूर्व में जब आप मुख्यमंत्री थे तब राज्य सरकार ने 15 वर्षों तक नक्सलवाद से कठिन लड़ाई की। दुर्भाग्यवश कांग्रेस की सरकार पांच साल के लिए आ गई। नक्सल समस्या से मुकाबला उनकी

प्राथमिकता था ही नहीं। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पांच सालों में 219 नक्सली मारे गये। वहीं हमारी सरकार के 14 महीनों के कार्यकाल के दौरान 305 से अधिक हार्डकोर नक्सली मारे गये, 972 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1183 नक्सली गिरफ्तार किए गए। (मेजों की थपथपाहट) हमारे बहादुर जवान पहले भी मोर्चे पर तैनात थे, अब भी मोर्चे पर तैनात हैं। उनमें नक्सलवादियों से लड़ने का भरपूर जज्बा पहले भी था, अब भी है, फिर क्यों कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। (मेजों की थपथपाहट) केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश से नक्सलवाद का सफाया करने की समय-सीमा मार्च, 2026 रखी है। हम संकल्पि हैं कि इस अवधि के पूर्व ही छत्तीसगढ़ से माओवाद का संपूर्ण सफाया कर देंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमने बोली का जवाब बोली और गोली का जवाब गोली से देने का निश्चय किया है। हमने सबसे अच्छी पुनर्वास नीति बनाई है। हमने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत की है। अध्यक्ष महोदय, अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित कई गांवों के बच्चों ने पहली बार राष्ट्रगान सुना और वहां पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। (मेजों की थपथपाहट) वहां पर पंचायत चुनाव में ग्रामीणों ने पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां गणतंत्र की विजय हुई। सुकमा जिले के कोंटाबला के केरलापेंदा में भी 20 सालों के बाद भगवान श्रीराम मंदिर के पट खुले और वहां पूजा प्रारंभ हुई। (मेजों की थपथपाहट) एक आयातीत भ्रष्ट क्रूर विचारधारा को एक आस्थावान समाज ने खारिज कर दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने नक्सली हिंसा से प्रभावित अति संवेदनशील गांवों को संवारने हेतु "नियद नेल्लानार योजना" प्रारंभ की, जिसका मतलब आपका अच्छा गांव होता है। हमने सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को चुना है। यहां 17 विभागों की 52 हितग्राहीमूलक योजनाओं एवं 31 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ लोगों को देना आरंभ किया। तेन्दूपत्ता संग्राहकों को अब चार हजार रूपये की जगह साढ़े पांच हजार रूपये संग्रहित राशि देंगे। (मेजों की थपथपाहट) सरकार की इच्छाशक्ति कितना कुछ बदल देती है, इसका उदाहरण इन गांवों में देखने को मिलता है । अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 31 फीसदी आबादी जनजातीय वर्ग की है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है । इन दत्तक पुत्रों के लिये कांग्रेसियों ने बहुत संवेदना व्यक्त की है, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं किया । मोदी जी ने इनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने की असाधारण पहल की है और प्रधानमंत्री जन-धन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के माध्यम से हजारों परिवारों को लाभान्वित किया । छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी ने देश में जनजातियों के समग्र विकास के लिये केन्द्रीय जनजातीय कल्याण मंत्रालय बनाया । अध्यक्ष महोदय, जाके पांव फटे न बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, मोदी जी ने देश के आम नागरिक का कठिन जीवन व्यतीत किया है, इस जीवन के अनुभव से मोती जो उन्हें मिले, उससे उन्होंने आम नागरिकों की सुविधा के लिये अनेक योजनायें बनाई । इनमें से एक ऐसी ही अनूठी योजना जल जीवन मिशन है, जल संकट आम जनता की आपदा

थी, यहां पिछली सरकार ने आपदा में अवसर खोज लिया । ऐसी जगहों में पानी की टंकी बना दी, पाईप लाईन बिछा दी, जहां पानी का स्त्रोत ही नहीं था, टंकी की गुणवत्ता जैसी भी हो, कमीशन भरपूर मिलना चाहिये, इस सूत्र वाक्य के साथ जल जीवन मिशन में जमकर [xx] हुई और कांग्रेस के कार्यकाल में काम नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के 5 सालों के कूशासन ने प्रदेश की छवि को बदनाम किया, इनकी सरकार के संरक्षण में महादेव एप खुलकर फला फूला । प्रोटेक्शन मनी जितनी तेजी से बढ़ती गई, सट्टे का कारोबार उतनी ही तेजी से फैलता गया । कांग्रेस की सरकार ने आबकारी नीति में ऐसे बदलाव किये, जिससे सरकारी राजस्व को ही चूना लगा दिया गया था । यह नंबर 2 का पैसा किस-किस रास्ते पर कहां-कहां पहुंच गया, इसकी जांच अभी एजेंसियां कर रही है । भ्रष्ट्राचार एक ऐसा वाईरस है, जो सबसे तेजी से फैलता है । छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट बना, जिसने अपने भ्रष्ट्राचार की भरपूर अनुभव का लाभ स्वयं तो लिया ही, दूसरे राज्य सरकारों को भी अपनी सेवायें दी है । झारखंड और दिल्ली की शराब नीति में बदलाव भी अमूमन ऐसे ही थे, साफ था कि एक ही सिंडिकेट हर जगह काम कर रहा था । अध्यक्ष महोदय, गांधी जी कहते थे कि धरती हर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन इससे मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं हो पाती है। सिंडिकेट ने आनन-फानन में पूर्ववती भाजपा सरकार की पारदर्शी ऑनलाईन पालिसी को बदल दिया और मैन्युअल ट्रांजिट पास आरंभ कर दिया । इसके बाद जो खेल हुआ, वह तो सबने देखा है । संसाधनों की ऐसी [xx] छत्तीसगढ़ ने पहले कभी नहीं देखी थी । अध्यक्ष महोदय, पत्रकार दीर्घा में हमारे पत्रकार भाई बैठे हैं, कांग्रेस के 5 साल के भयावह अनुभव से वे सभी गुजरे हैं । जब पत्रकार भाईयों ने भ्रष्ट्राचार को उजागर करते हुये अपनी खबर बनाई तो सी.एम.हाऊस से पत्रकारों को हटाने के लिये फोन जाने लगे । कई पत्रकार बेरोजगार हो गये, सच लिखने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, उन्हें जेल में भी डाल दिया गया । अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सदन में मेरी फोटो को लेकर टिप्पणी की थी । मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरा विश्वास जमीन पर काम करने में ज्यादा है, काम अच्छा होगा तो मीडिया निश्चित रूप से फोटो अपने आप छाप देगा । (मेजों की थपथपाहट) मुझे भूपेश जी का कार्यकाल याद आता है । छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे ज्यादा प्रचार का बजट उनके कार्यकाल में था । दिल्ली से लेकर रायपुर तक और रायपुर से लेकर पाटन तक विज्ञापन में केवल वही थे । जमीन पर कुछ काम नहीं हुआ, परिणाम हम सबके सामने है । आज वे गायब हैं और हम लोग इधर हैं । अध्यक्ष महोदय, आज कुछ परिवारवाद पार्टी के लोग संविधान की दुहाई देते हुये संविधान की किताब लिये घूमते हैं । इन्हीं लोगों ने आज से 50 साल पहले इमरजेंसी लगाकर देश को तानाशाही की ओर ढ़केल दिया था । (शेम-शेम की आवाज) हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने आपातकाल के कठिन दौर पर संविधान की मशाल को बूझने नहीं दिया । (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस की सरकार ने इन लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान निधि भी रोक दी थी । अपने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान निधि हमारी सरकार ने पुन: प्रारंभ की है । अध्यक्ष महोदय,

हमने भ्रष्ट्राचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया है । खनिजों का ऑनलाईन ट्रांजिट पास पुन: प्रारंभ किया (मेजों की थपथपाहट) भ्रष्टाचारियों में आज ए.सी.बी. का खौफ है, वह पहले कभी नहीं रहा । हमने आबकारी की पुरानी नीति को समाप्त किया और नई नीति के चलते फर्जीवाड़े पर रोकथाम लगी और आबकारी राजस्व दोगुना हो गया । हमने खरीदी प्रक्रिया के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जैम पोर्टल से खरीदी अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के साथियों ने धान खरीदी को लेकर कितना दुष्प्रचार किया । कोई यह भी असत्य कथन फैला रहे थे कि किसान भाईयों को पैसा नहीं मिल रहा है । इस असत्य कथन ही हवा ही निकल गई । धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के बाद ही किसान भाईयों के खाते में अंतर की राशि भेजने का काम सरकार ने किया । (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस के सदस्य तो अभी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी नहीं हो रही थी तो 25,49,000 किसान कौन हैं, जिन्होंने अपना धान बेचा । (मेजों की थपथपाहट) धान खरीदी नहीं हो रही थी तो 149 लाख, 25 हजार मेट्रिक टन धान किसने बेचा ? अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार में गौठानों के निकट बड़े-बड़े होल्डिंग लगे होते थे तथा गोबर और गो मूत्र की खरीदी के दावे होते थे । जब भाजपा का दल गौठानों में सत्यता देखने के लिए जाता था तो नील बंटे सन्नाटा नजर आता था, गांव कहीं नजर नहीं आती थी । हमारी सरकार ने गो वंश को बढ़ावा देने के लिए एनडीटीवी से एक एमओयू किया है । अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने माताओं और बहिनों से जो वायदे किये थे, वह नहीं निभाए । हमने माता और बहिनों से वादा किया था कि हम हर महीने 1 हजार रूपए महतारी वंदन योजना का देंगे, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है । आज 59 लाख, 54 हजार माता एवं बहिनों को इस योजना का लाभ दे रहे हैं । हमारा यह छोटा सा प्रयास उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान के कटोरे में कोई भूखा न सोए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना आरंभ की और उस समय आप स्वयं मुख्यमंत्री थे । (मेजों की थपथपाहट) यह काम इतने व्यवस्थित तरीके से हुआ कि छत्तीसगढ़ देश में खाद्य सुरक्षा का मॉडल राज्य बन गया । हमारी सरकार जरूरतमंद 68 लाख परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन प्रदान करेगी ।

अध्यक्ष महोदय, जब लोग अपनी परम्पराओं से कट जाते हैं तो एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाता है, जो अपनी ही संस्कृति और ऐतिहासिक मूल्यों का तिरस्कार करने लगता है । यह दोष उनका नहीं है, यह शिक्षा पद्धति का दोष था, जिसने राष्ट्रवादी मूल्यों को शिक्षा से नहीं जोड़ा । इतिहास की किताबों में मुगलों की हर बादशाह का एक चैप्टर होता था, वहीं मराठा छत्रपतियों को केवल एक चैप्टर में निपटा दिया जाता था । कुछ महीनों पहले *स्वातंत्र्य* वीर सावरकर फिल्म आई थी । इसमें वीर सावरकर के

कठिन संघर्ष को दिखाया गया है । (मेजों की थपथपाहट) अभी छावा फिल्म आई है । संभाजी महाराज ने जिस तरह से राष्ट्रवादी मूल्यों के लिए काम किया, उनकी शहीदगी इस फिल्म में दिखाई गई है । जिन लोगों ने यह फिल्म देखी, उन्होंने यह प्रश्न किया कि ऐसे महापुरूषों के उज्जवल इतिहास को क्यों छिपाया गया?

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल सुधार किये हैं । हमारे बच्चे अब विस्तार से देश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में जानेंगे । प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि विरासत और विकास की पटरी पर ही देश आगे बढ़ता है । हमने छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है । शिक्षाविदों के अनुभव तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के मुताबिक यदि स्थानीय भाषाओं को बच्चों को पढ़ाई कराई जाये तो उनकी सीखने की गति काफी तेज हो जाती है । छत्तीसगढ़ का परिवेश बहुभाषी है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं के अनुरूप कक्षा पहली एवं दूसरी में विभिन्न स्थानीय भाषाएं एवं चार प्रांतीय भाषाओं में द्विभाषी पुस्तकें तैयार की गई हैं । परिवार को किसी बच्चे की पहली पाठशाला मानी जाती है । स्कूल में बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षकों का नियमित संवाद बना रहे, इसके लिए पैरेंट्स-टीचर मीटिंग आरंभ कराई है । 5वीं एवं 8वीं की केन्द्रीकृत परीक्षा करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई पुन: लय में आई है। (मेजों की थपथपाहट) उच्च शिक्षा में भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है। हमने एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई की सुविधा हिन्दी माध्यम से आरंभ की है।

अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान योजना के रुप में प्रधान मंत्री जी ने करोड़ों भारतीयों को स्वास्थ्य सुविधा के दायरे में लाया है। अब 70 वर्ष से अधिक नागरिकों को भी इसकी सुविधा मिल रही है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ में 77 लाख, 20 हजार परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का लाभ मिल रहा है। मेडिसिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत अटल नगर नवा रायपुर में हमारी सरकार ने 200 एकड़ भूमि चिन्हांकित की है।

अध्यक्ष महोदय, किसी राज्य में निवेश तभी होता है, जब उस राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बढ़िया हो। एक ऐसी औद्योगिक नीति हो, जो नए जमाने के अनुरूप हो, डिजिटल गवर्नेंश हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, ताकि एन.ओ.सी. के लिए बार-बार भटकना न पड़े। हमारी सरकार ने इन सभी बातों को अपनाते हुए नई औद्योगिक नीति बनाई, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में निवेश अब बेहद आकर्षक हो गया है। (मेजों की थपथपाहट) हमारी नई औद्योगिक नीति में सरगुजा और बस्तर में उद्योग लगाने पर विशेष रियायत दी गई है। नई औद्योगिक नीति में सेवानिवृत्त अग्निवीर, आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सल हिंसा से प्रभावित लोगों के उद्यम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को हमने मात्र एक रुपए प्रति एकड़ की दर पर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि देने का प्रावधान रखा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में टूरिज़्म की भरपूर संभावना है। टूरिज़्म को उद्योग का दर्जा देने और होम स्टे में विशेष रियायत देने से यहाँ उद्यमी आकर्षित होंगे। (मेजों की थपथपाहट) देश के तीसरे सबसे बड़े टाईगर रिजर्व गुरुघासीदास तमोर पिंगला के निर्माण से इको टूरिज़्म में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

अध्यक्ष महोदय, चौबीस घंटे-सातों दिन दुकानों के खुले रहने के निर्णय की वजह से व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से हमारा फोकस विशेष रुप से युवाओं के रोजगार श्रृजन पर है। हमें उम्मीद है कि अगले पांच सालों में ढाई लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे पांच लाख लोगों के लिए रोजगार की संभावना बनेगी। रायपुर के साथ ही दिल्ली और मुंबई में हमने इन्वेस्टर कनेक्ट किए हैं, इससे हमें अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम अटल नगर नवा रायपुर को आई.टी. हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। हम सरप्लस पॉवर स्टेट हैं। क्लाइमेट चेंज और ए.आई. दुनिया के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। इन दोनों चुनौतियों को हमारा राज्य अवसर के रुप में इस्तेमाल कर रहा है। क्लाइमेट चेंज के चलते पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिकल वाहन की मांग बढ़ेगी। इन्हें चार्ज़ करने के लिए बिजली चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारा राज्य आज पहला ऐसा राज्य है, जहां लीथियम ब्लॉक का ई-ऑक्शन से आवंटन हुआ है। लीथियम इलेक्ट्रिकल वाहनों की बैटरी के लिए सबसे जरुरी मिनरल है।

अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। हमारी सरकार ने आगामी 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है तथा इस पर गंभीरता से अमल भी हो रहा है। प्रदेश में बिजली कटौती बिल्कुल भी नहीं हो रही है। राज्य के किसानों को 18 घंटे मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे राज्य में अब तक 12 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। मोर बिजली एप, 1912 सेवा एवं लोकल कॉल सेंटर आदि उपायों के भी उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा जोर स्किल डेव्हलपमेंट पर है। 484 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की 160 आई.टी.आईस. को हम मॉडल आई.टी.आई. के रूप में बदल रहे हैं। इसके चलते अब छत्तीसगढ़ में पर्याप्त कुशल मानव संसाधन मिल पायेंगे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों के डिस्प्ले के लिए तथा शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल स्थापित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना की है। हमने शासन के हर स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस को अपनाया है, हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच किया है। शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में इससे मदद मिल रही है। हमने विभागीय कार्यों में

डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये 266 करोड़ रूपये का बजट रखा है। हम ई-ऑफिस प्रणाली लेकर आये, इसमें तय समय-सीमा में काम होता है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहती। केंद्र सरकार की योजनाओं के लिये राशि जारी करने, वितरित करने और बेहतर नगद प्रबंधन के लिये हमने जस्ट इन टाइम मॉडल अपनाया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिये हम सुगम एप्लीकेशन लेकर आये हैं। स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को भूमि संबंधी सर्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने जो रिफॉर्म्स किये हैं, उसके चलते भारत सरकार से हमें 6,301 करोड़ रूपये की राशि इंसेंटिव के रूप में प्राप्त हुई है। (मेजों की थपथपाहट) हमारा फोकस पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने को लेकर है। पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाता है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय के लिए 23,600 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह पिछले वर्ष की 16 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 48 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दिखाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जो नवाचार किये हैं, उनकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। जनभागीदारी में जल संचय के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। (मेजों की थपथपाहट) हमारे खनिज ऑनलाईन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। हमारे प्रदेश को इण्डिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड भी मिला है।

अध्यक्ष महोदय, बरसों बाद बस्तर में उत्सव का वातावरण लौटा है। बस्तर ओलंपिक में बस्तर के खिलाड़ियों के जोश और उत्साह को पूरे देश ने देखा है। 1,65,000 प्रतिभागियों ने खेल में हिस्सा लिया, इसमें वे लोग भी थे जो नक्सल हिंसा में दिव्यांग हो चुके हैं। कांग्रेस सरकार के समय के लंबित खेल अलंकरण पुरस्कार हमने पुन: प्रारंभ किया है। खेलो इण्डिया के साथ हमने सेंटर भी आरंभ किये हैं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन भी बीते एक साल में किये हैं। हमने इण्डियन रोड कांग्रेस आयोजित किया, इसमें माननीय केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री, श्री नीतिन गडकरी ने 20,000 करोड़ की अधोसंरचना परियोजनाओं की घोषणा की। (मेजों की थपथपाहट) क्लाईमेट चेंज कॉनक्लेव में हमने क्लाईमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिये विस्तार से चर्चा की। क्लाईमेट चेंज के चलते ग्रीन स्टील पर पूरी दुनिया का फोकस है। हमारे यहां ग्रीन स्टील इंटरनेशनल समिट का आयोजन भी हुआ। हमने ऑल इण्डिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का भी आयोजन किया। हमने अपने प्रदेश में नेशनल बोर्ड चैम्पियनशिप का भी आयोजन किया।

अध्यक्ष महोदय, हमे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि हमने प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने वाले हमारे श्रद्धालुओं के लिए छत्तीसगढ़ पवेलियन में विशेष व्यवस्था की। (मेजों की थपथपाहट) साढ़े 4 एकड़ में फैले इस पवेलियन में लोगों के रूकने खाने-पीने की सुविधा थी। सबने इसे विशेष रूप से सराहा है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हम सब को महाकुंभ में आमंत्रित कर दिव्य स्नान के लिए पूर्ण लाभ का अवसर दिया। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस के राष्ट्रीय

अध्यक्ष ने कहा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है ? क्या खाना मिलता है ? मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि 66 करोड़ भारतीय जो अपनी सुख, समृद्धि की कामना के लिए महाकुंभ गये थे, क्या वह गंगा मैया की भक्ति में वहां नहीं गये थे ? जो लोग पैसे कौड़ी की भाषा समझते हैं, वह कभी-भी आस्था की भाषा नहीं समझ सकते। (मेजों की थपथपाहट) हमने राजिम कुंभ कल्प का वैभव पुन: लौटाया। वहां सुंदर संत समागम हुआ। हमारी सरकार ने अयोध्या धाम श्री राम लला दर्शन योजना आरंभ की है। इसके माध्यम से अभी तक 20,000 से अधिक श्रद्धालु श्री राम और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन का पूर्ण लाभ ले चुके हैं। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान भूपेश जी ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि यह तो हमारी सरकार के समय की योजनाएं थीं। मुझे यह लगा कि उनकी ज़ुबान फिसल गई। शायद वह यह कहना चाह रहे हों कि हमारी सरकार के समय में ऐसी योजनाएं बनती तो प्रदेश का जनादेश कुछ और होता। (मेजों की थपथपाहट) मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही हैं, उनसे उनका भ्रम दूर हुआ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है और हमारी यह विधान सभा भी अपना रजत जयंती वर्ष मना रही है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम सब कड़ी मेहनत करें । निश्चय ही जब भविष्य में विधान सभा अपना स्वर्ण जयंती मनाएगी तब विकसित छत्तीसगढ़ की ईमारत भी मूर्त रूप ले लेगी। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। मैं सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका सहयोग निरन्तर बना हुआ है और यह आगे भी बना रहे। माननीय राज्यपाल महोदय जी को उनके अभिभाषण के लिए पुन: धन्यवाद् देता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- मैं, समझता हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक साथ मत ले लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- "माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर प्रस्तुत समस्त संशोधन स्वीकृत किये जायें।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- "माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

समय
3.32 बजे

अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

श्री चिंतामणि महाराज, सांसद, लोक सभा

अध्यक्ष महोदय :- अध्यक्षीय दीर्घा में श्री चिंतामणि महाराज, सांसद उपस्थित हैं। मैं उनका सदन की ओर से स्वागत करता हूँ। (मेजों की थपथपाहट)

अशासकीय संकल्प, माननीय धर्मजीत सिंह अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

समय
3.33 बजे

अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये।"

श्री धर्मजीत सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये। "

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बिलासपुर से रीवा के लिए और रीवा से बिलासपुर तक के ट्रेन की सुविधा तो है...।

कृषि मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है। इसी विषय में मैं, अपनी बात कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इसी संकल्प में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामविचार नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय में एक व्यवस्था की बात है। मैं, आपकी अनुमति से यह चाहता था कि दो अशासकीय संकल्पों पर चर्चा होनी है, वह एक ही प्रकृति के हैं। इन दोनों को क्लप (एक साथ) करके भी संकल्प को पास किया जा सकता है या चर्चा की जा सकती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीनों अशासकीय संकल्पों को क्लप किया जा सकता है। तीनों अशासकीय संकल्प रेल से ही संबंधित हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों अशासकीय संकल्पों की प्रकृति अलग-अलग है और इन दोनों का मसला भी अलग-अलग है। इसलिए इसमें 5-5 मिनट का समय लगेगा, यह ज्यादा नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि रीवा से बिलासपुर के बीच एक मात्र ट्रेन संख्या 18248 है, जो वहां से रात्रि को 10.00 बजे चलकर, प्रात: 9.45 के बीच चलती है। इस बीच में वह आकर बिलासपुर में रूक जाती है। फिर बिलासपुर से जो दुर्ग तरफ के यात्री हैं, आधे छत्तीसगढ़ के यात्री हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई और रायपुर में इस ट्रेन के माध्यम से बस्तर के लोग भी इससे जुड़ने वाले हैं। अगर इससे जुड़ने के लिए उन्हें दुर्ग तक सुविधा दे दी जाये तो यह ट्रेन जो अनावश्यक रूप से बिलासपुर में आकर रूकती है उसके माध्यम से हम अपने छत्तीसगढ़ के लोगों को विंध्य प्रदेश, विंध्याचल, रीवा और शहडोल की तरफ जाने के लिए एक व्यवस्था दे सकते हैं। यह ट्रेन बिलासपुर जोन की है। जब यह ट्रेन बिलासपुर जोन चलती है तो वहां रीवा में जाकर 10 से 12 घण्टे तक के खड़ी रहती है इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि इस ट्रेन को बिलासपुर जोन से ट्रांसफर करके जबलपुर जोन को भेजा जाये। जो वहां 10-12 घण्टे खड़ी रहती है उसको रि-शेड्यूल करके यहां पर भेजा जाना चाहिए ताकि हमारे विन्ध्य प्रदेश के रहने वाले बहुत से लोग और छत्तीसगढ़ के भी वह लोग जो चित्रकूट, सतना, मैहर जाना चाहते हैं और रीवा से प्रयागराज के लिए जाना चाहते हैं, उनको एक बढ़िया बेहतर कनेक्टीविटी उपलब्ध हो। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि यह समाज के लोग आपसे भी मिले थे। आप भी इसमें पहल किये हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी सहित पूरा सदन यहां पर उपस्थित है। हम इस सेवा का सिर्फ विस्तार चाहते हैं। इसमें सरकार की तरफ से कोई अन्य खर्च नहीं है। बल्कि 12 घंटे जो ट्रेन फालतू खडी रहती है, वह वहां से चले। ऐसा भी नहीं है कि दुर्ग जाकर के उस ट्रेन को कोई व्यवस्थित करने में तकलीफ हो, क्योंकि दुर्ग से छपरा सारनाथ एक्सप्रेस चलती है। दुर्ग स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो किसी भी ट्रेन के गंतव्य के लिए छोड़ने के लिए सक्षम है। इसलिए यह ट्रेन न केवल छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले विन्ध्याचल क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित हो सकती है। मैं समझता हूं कि इसमें रेलवे विभाग को कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं जायेगी। क्योंकि बिलासपुर से कटनी के बीच जो रेलवे लाईन है, उसका भी तीन लाईन का विस्तार हो चुका है। बिलासपुर से जो दुर्ग की तरफ आयेगी या बिलासपुर से जो हावड़ा की तरफ जाती है, हावड़ा-बांबे रूट बहुत मजबूत, विकसित है, बहुत चौड़ा है। तो इसमें इस ट्रेन को चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी, इसमें पुरजोर तरीके से यह लिख करके जरूर भेजा चाहिए कि यह ट्रेन जो अभी वर्तमान में चल रही है, वह बिलासपुर जोन के कंट्रोल में है, इसका कंट्रोल जबलपुर जोन को दे दिया जाना चाहिए। जबलपुर जोन में जो 12 घंटे रीवा में खड़ी रहती है उसका सदुपयोग करके और ट्रैफिक का ऐसा सिस्टम बनाकर बिलासपुर तक चलने वाली ट्रेन को दुर्ग तक भेजा जाना चाहिए। ताकि भाटापारा, रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर और बस्तर के लोग जो उस दिशा में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह ट्रेन बहुत ही कारगर होगी। यह बहुत ही जनउपयोगी ट्रेन होगी। इस जनहित के मुद्दे को दिल्ली की सरकार के रेलवे डिपार्टमेंट को बहुत गंभीरता से लेकर के हमारे यहां रहने हजारो

भाईयों को जो विन्ध्याचल के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, धर्मप्रेमी छत्तीसगढ़ है। हम लोग मैहर की माता के दर्शन के लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब वह ट्रेन बिलासपुर तक आती है तो वहां से उतरकर दुर्ग आने वालों को ट्रेन संख्या 12834 अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन मिलती है जो वहां से 12 बजे चलती है। आदमी वहां पर 3-4 घंटे परिवार सहित तकलीफ पाते हैं। अगर वह डॉयरेक्ट ट्रेन होगी तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। यह जनहित का मुद्दा है। माननीय मंत्री जी, इसमें कोई किंतु, परंतु नहीं होना चाहिए। इसको प्रस्ताव पास करके भेजना चाहिए। हम दिल्ली की सरकार से यह विनम्रतापूर्वक मांग करते हैं कि सदन के इस अभिमत को दिल्ली की सरकार गंभीरता से ले। बिलासपुर-रीवा या रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक बढ़ाने के लिए अपनी सहमति और व्यवस्था प्रदान करें ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित हो सके और एक अच्छी ट्रेन मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मारे कोयला की गाड़ियों के पैसेंजर ट्रेन के लिए गुंजाइश बहुत कम है। अगर इसी तरह से गुंजाइश निकालेंगे तभी हमको सुविधा मिल पायेगी। जो ट्रेन रीवा से बिलासपुर आती है, उसे दुर्ग तक भेजने में दो से ढाई घंटे लगना है और दो से ढाई घंटे वापस आने में लगना है। वह ट्रेन वहां पर 12 घंटे खड़ी रहती है। अगर हम उसमें 5 घंटे घटा भी देंगे तो 7 घंटे में एक ट्रेन की धुलाई, मेन्टेनेंस और उसको सही तरीके से तैयार करके यहां आने और जाने के लिए किया जा सकता है इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक सभी साथियों से, माननीय मुख्मयंत्री जी से भी आग्रह करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी ने इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। आपकी ही कृपा से हम इस सदन में इसको चर्चा कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इतने बड़े नेता जिनके पास लोग आये हैं, पूरे प्रदेश के लोग आ करके उनसे अपनी फरियाद किये हैं, अपना मेमोरेंडम दिये हैं तो इसको तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके दिल्ली भेजना जरूरी है और जनहित के लिए ये मांग अत्यन्त आवश्यक है, अनिवार्य है। हम दिल्ली की सरकार से भी यह आग्रह करते हैं कि इसको वह स्वीकार करके हमारे छत्तीसगढ़ के एक आधे हिस्से को दुर्ग, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, कांकेर और जगदलपुर के लोगों को भी इस सुविधा से युक्त करें और हमें हमारी सुविधा दें । हम देश की बहुत सेवा करते हैं । हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आमदनी देने वाला जोन बिलासपुर जोन है । अध्यक्ष महोदय, हम कोयला, सीमेंट, बॉक्साईट, लोहा सब कुछ करते हैं तो एक हमारी इस मांग को दिल्ली की सरकार भी गंभीरता से लेगी ऐसी मैं आशा करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने हेतु समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री भईयालाल राजवाड़े (बैकुंठपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरी भी चर्चा है । चिरमिरी से बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाया जाए, यह ट्रेन भी दिनभर बिलासपुर में खड़ी रहती है इससे राजधानी तक के लोगों को आने-जाने में मदद मिलेगी । आपसे मेरा यह आग्रह है कि इसको भी

जोड़कर के उसी साथ भेजा जाए । धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । मंत्री जी जवाब देंगे ।

श्रम मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं वक्तव्य पढ़ने से पहले एक विषय रखना चाह रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिए-बोलिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारी रेल परियोजनाओं को भारत सरकार से अनुमति लेकर प्रारंभ कराया । अभी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है । मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के लिए 8 रेल परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की है इसमें हमारे छत्तीसगढ़ east railway limited से अंतर्गत खरसिया-धरमजयगढ़ 131 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ east railway limited अंतर्गत धरमजयगढ़-उरगा 62 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ east based railway limited अंतर्गत गेवरा-पेण्ड्रा रोड 135 किलोमीटर, जगदलपुर-रावघाट railway project limited 140 किलोमीटर, कठघोरा-डोंगरगढ़ परियोजना 295 किलोमीटर, परसामातिन परियोजना 54 किलोमीटर, अंबिकापुर-बरवाडीह परियोजना 182 किलोमीटर, खरसिया-नारायणपुर परमालकासा परियोजना 325 किलोमीटर का रेल का विस्तार छत्तीसगढ़ में हो रहा है इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ को इतनी बड़ी सौगात मिली है । (मेजों की थपथपाहट) और हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य धर्मजीत सिंह जी ने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव रखा है । मध्यप्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के लोगों को निवास रोज़गार के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में आवागमन होता रहता है । आमजनों के लिए सुविधाजनक एवं कम खर्चीले विकल्प के रूप में रेल्वे यातायात का महत्वपूर्ण साधन है । रीवा से बिलासपुर के बीच एकमात्र ट्रेन संख्या 18 हज़ार 248 रात्रि 10.05 बजे से प्रात: 9.00 बजे के बीच चलती है । रीवा से यात्रा करने वाले जिन यात्रियों को रायपुर, भिलाई, दुर्ग एवं राजनांदगांव तक जाना होता है उसके लिए सीधी ट्रेन सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है । ऐसे यात्रियों को दूसरी ट्रेन लेकर सफर करना पड़ता है । उपरोक्त ट्रेन से उतरने के पश्चात् दुर्ग या राजनांदगांव के लिए पहली ट्रेन संख्या 12 हज़ार 834, अहमदाबाद superfast express, मध्याह्न 11.50 बजे है इससे स्पष्ट है कि यदि रीवा-बिलासपुर express का दुर्ग या राजनांदगांव तक विस्तार किया जाता है तो वहां तक जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी अतः केंद्र सरकार से इस सूचना के अनुसार अनुरोध किया जाना उचित होगा कि आवश्यक समीक्षा करते हुए रीवा-बिलासपुर express का विस्तार किया जावे । मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इसे ध्वनि मत से पारित करें । (मेजों की

थपथपाहट) एक और हमारे वरिष्ठ सदस्य जी ने बात रखी कि चिरमिरी-बिलासपुर जो ट्रेन चलती है, उसे दुर्ग तक जोड़ा जाए तो उसको भी इसमें समाहित करने का कष्ट करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- एक संशोधन माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, उस संशोधन के सहित इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यथा संशोधित प्रस्ताव यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "रीवा-बिलासपुर एक्सप्रेस को एवं चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस को दुर्ग तक विस्तारित किया जाये।"

यथा संशोधित संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक-18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक-18206 का व्हाया अयोध्या धाम प्रतिदिन परिचालन किया जाये।"

श्री रिकेश सेन (वैशाली नगर) :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि "दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक-18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक-18206 का व्हाया अयोध्या धाम प्रतिदिन परिचालन किया जाये।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से केंद्र सरकार के प्रयासों से 500 साल बाद भगवान राम की वापसी उनके मंदिर पर हुई है और हम सब लोग अपने आराध्य देवता को मानते हैं। जिस प्रकार से अयोध्या के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण कई प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें सिर्फ एक मात्र गाड़ी है, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 18205, जो सप्ताह में केवल 1 दिन ही जाती है और इसके साथ एक ही दिन सप्ताह में शनिवार को वापसी आती है, जो 18206 क्रमांक है। अभी तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है। मुझे तो लगा था कि जब यह संकल्प आएगा तो हमारे विपक्ष के साथी भी बैठे होंगे, लेकिन देखिये भगवान राम का आशीर्वाद ऐसे सनातन विरोधी, ऐसे प्रस्ताव के समय वे हैं ही नहीं, क्योंकि हमेशा उन्होंने सनातन का विरोध किया है और ये सौभाग्य है..।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये तो सनातन को डेंगू बोलते हैं।

श्री रिकेश सेन :- बिल्कुल, और ये स्नान करने भी नहीं गये।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये डेंगू बोलते हैं।

श्री रिकेश सेन :- मैंने तो इस बात को लेकर सोचा था कि कम से कम धन्यवाद प्रस्ताव इस बात का लेकर आते कि 144 साल बाद इतना व्यवस्थित तरीके से महाकुंभ हुआ था। मैं इस बात को सोच रहा था कि वे विष्णुदेव साय जी की सरकार को धन्यवाद देंगे कि पहली सरकार है, जो प्रयागराज में वहां पर जाकर इतनी अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़वासियों के लिए विष्णुदेव साय जी की सरकार ने किया। लेकिन वे सनातन विरोधी यहां पर नहीं हैं। मैं सदन से निवेदन करता हूं एवं आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस विषय को जोकि प्रतिदिन अयोध्या जाने के लिए ट्रेन चले, से संबंधित है, क्योंकि ये मामला केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। अतः मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जन भावनाओं की दृष्टि को देखते हुए आप सभी लोग सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजें और आप इस बात को मानकर चलिए कि असुविधा होने के कारण, ट्रेन नहीं जाने के कारण कई लोग बाई रोड भी जाते हैं। कई लोग अपनी-अपनी बस की सुविधाओं से जाते हैं। कई लोगों को कई ट्रेन बदलनी पड़ती है। लेकिन अगर हम सीधी ट्रेन अयोध्या तक भेजते हैं तो मुझे लगता है कि ये बड़ा काम उन श्रद्धालुओं के लिए होगा। उन सनातन धर्म से जुड़े लोगों के लिए होगा और इस बात को भी मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस प्रकार से चाहे वह उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे वह मथुरा का कॉरिडोर हो, चाहे वह बनारस का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या का कॉरिडोर हो, निश्चित रूप से इसमें श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है, 66 करोड़ लोगों ने अगर प्रयागराज में स्नान किया है तो उतने ही लोगों ने बाकी जगह भी दर्शन किया है, लेकिन कहीं न कहीं ट्रेन की सुविधा नहीं होने के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है, पूरे सदन से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि इस संकल्प को पारित करके सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को भेजा जाए। मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि यह एक बड़ा विषय है, कभी-कभी सरकारों को ध्यान में ऐसा विषय नहीं आ पाता है । लेकिन ऐसा विषय यदि छत्तीसगढ़ के सदन से जाएगा तो एक बड़ी पहल होगी । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेमेतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अशासकीय संकल्प सूचना क्रमांक 6 के अधीन यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 व्हाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए । इस विषय पर जो अशासकीय संकल्प माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन जी ने लाया है, यह अपने आप में अद्भुत विषय है । आपको याद दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने भांचा राम के दर्शन के लिए जो श्रवण कुमार की भूमिका निभा रही है, उसकी प्रतिपूर्ति के उपलक्ष्य में या उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस ट्रेन का परिचालन प्रतिदिन हो, यह आवश्यक है । आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि साढ़े पांच सौ साल की आध्यात्मिक गुलामी के बाद हम सबके भांचा राम टेंट यानी टाट से ठाठ यानी महल में पहुंचे । ऐसे अवसर पर छत्तीसगढ़ का जन-जन उत्साह से लबरेज़ है और ऐसे समय में वह अयोध्या दर्शन करना चाहता है ।

परंतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उससे यह संख्या पूर्ति नहीं हो सकती । क्योंकि एक ट्रेन में लगभग 800 दर्शनार्थी ही जा सकते हैं, जो यदि मासिक तौर पर लगातार 30 दिन चले तो 23-24 हजार लोग ही मासिक तौर पर दर्शन का लाभ ले सकते हैं । ऐसे में छत्तीसगढ़ का जो जन-जन है, जो अयोध्या धाम के भव्य और दिव्य स्वरूप का, भगवान रामलला के विग्रह स्वरूप का दर्शन करना चाहता है जो श्याम रंग में, बाल्यकाल की मूर्ति के रूप में स्थापित हैं । छत्तीसगढ़ की जनता अपने भांचा राम के दर्शन करना चाहती है । मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से ध्वनिमत से पास करें, ताकि छत्तीसगढ़ जो कि भगवान राम का ननिहाल है, भांचा के विग्रह स्वरूप का दर्शन करके लाभ प्राप्त कर सकें । आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री रिकेश सेन :- अध्यक्ष महोदय, इसी पर मेरा एक निवेदन और है । यह सदन इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के रेल मंत्रालय को भेजेगा । चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि यह बड़ा गंभीर विषय है । इस विषय पर आप खुद, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से और रेल मंत्री जी से वार्तालाप करें । आप निश्चित मानिए कि जैसे ही पता चलेगा कि प्रतिदिन यह ट्रेन चल रही है तो छत्तीसगढ़ में एक खुशी का माहौल हो जाएगा । हर जगह से जय श्री राम, जय श्री राम के नारे गूंजेंगे । बहुत बहुत धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ । यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक 18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक 18206 व्हाया अयोध्या धाम का प्रतिदिन परिचालन किया जाए ।

उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छा अशासकीय संकल्प है । चूंकि भगवान श्री राम जी के अयोध्या धाम तक ट्रेन की बात आई है । निश्चित तौर पर दुर्ग से अयोध्या होते हुए नौतनवा जाने वाली ट्रेन संख्या 18205 दुर्ग से नौतनवा दिन गुरूवार से दुर्ग से प्रस्थान करती है । नौतनवा से अयोध्या होते हुए ट्रेन 18206 नौतनवा-दुर्ग एक्सप्रेस रविवार को दुर्ग पहुंचती है । दुर्ग एवं अयोध्या के बीच उपरोक्त अतिरिक्त अन्य कोई ट्रेन नहीं है । आम जन के लिए सुविधाजनक एवं कम खर्चीले विकल्प के रूप में रेलवे यातायात का महत्वपूर्ण सावधन है । राज्य में हिंदू आबादी की बहुलता को दृष्टिगत् रखते हुए धार्मिक पर्यटन के लिए उपरोक्त मार्ग पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना संभावित है । अतएव केन्द्र सरकार से इस सूचना के अनुसार अनुरोध किया जाना उचित होगा कि आवश्यक समीक्षा करते हुए सप्ताह के अन्य दिनों में भी उपरोक्त ट्रेनों के परिचालन की दिशा में कार्रवाई की जाए। मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इसको ध्वनिमत से पारित करें। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि दुर्ग-नौतनवा गाड़ी क्रमांक-18205 व वापसी गाड़ी क्रमांक-18206 का व्हाया अयोध्या धाम प्रतिदिन परिचालन किया जाये।"

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- अशासकीय संकल्प संख्या- 03, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल। अनुपस्थित।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 03 मार्च, 2025 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(अपरान्ह 3 बजकर 56 मिनट पर विधान सभा सोमवार, दिनांक 03 मार्च, 2025 (फाल्गुन 12, शक संवत् 1946) के पूर्वान्ह 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 28 फरवरी, 2025

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं